वर्तमान कमल ज्योति

सदैव अटल, कोटिशः नमन्!

जनपद स्तरीय
किसान सम्मान दिवस

AgriGation
FPO LEADERSHIP SUMMIT & EXHIBITION
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
राष्ट्रीय किसान दिवस, 23 दिसम्बर 2022

सुराज की विचार यात्रा
वर्तमान कमल ज्योति

वर्तमान
कमल ज्योति

संरक्षक
श्री भूपेन्द्र सिंह
सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी
प्रबन्ध/कार्यकारी सम्पादक
राजकुमार
प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह
पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय
कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक
नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

www.up.bjp.org
bjpkamaljyoti
bjpkamaljyoti
@bjpkamaljyoti

नमस्तुते !

2023
की
हार्दिक शुभेच्छा !

गलत इतिहास को बढ़ावा?

आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतीय इतिहास पर विमर्श खड़ा हो गया है। भारतीय इतिहास पुर्नलेखन के प्रयास तेज हुए है। विशेष कर कुछ इतिहासकारों द्वारा गुलामी के इतिहास को राष्ट्रीय ढंग से प्रस्तुत कर देश के राष्ट्रीय चरित्र को बिगाड़ने के प्रयास हुए हैं। आजादी के बाद भी इतिहास की विसंगतियों के दूर करने के प्रयास नहीं हुआ। विशेष कर वामपंथी लेखकों द्वारा एकतरफा प्रयास हुआ। लेकिन गृहमंत्री अमितशाह जी ने एक सम्मेलन में कहा था कि आखिर उचित, समग्रतावाला, सही इतिहास लिखने से हमें किसने रोका? ये दोषारोपण बन्द होना चाहिए। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अयोजित '**वीर बाल दिवस**' कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मुगलिया सल्तनत पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि उस दौर में औरंगजेब के आतंक के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। लेकिन उनके दो साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया।

दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी इसलिए की गई, क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। लेकिन भारत के वो बेटे वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आततायी मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। इन प्रेरणादायी घटनाओं को इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता।

देश में पहली बार शुरू '**शहीदी सप्ताह**' के बीच '**वीर बाल दिवस**' को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बोले कि साहिबजादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी '**शौर्यगाथा**' को भुला दिया गया। लेकिन अब '**नया भारत**' दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को '**वीर बाल दिवस**' के तौर पर घोषित करने का मौका मिला।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी अगर पाठ्यक्रम में दिगभ्रमित करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। तो ये किसका दुर्भाग्य है? हमारे अन्दर हीन भावना आखिर कब तक पैदा होती रहेगी। प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव वर्ष में स्वाधीनता आन्दोलन के अनेक अनाम क्रान्तियों, आन्दोनल की बात, अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। जिनसे प्रेरणा मिलती। आज आवश्यकता है? भारतीय जीवन मूल्यों संस्कारों के आधार पर भारतीय इतिहास का पुर्नलेखन आवश्यक है। इस राष्ट्रयज्ञ को देश के विद्वानों, लेखकों, इतिहासकारों को पूरा करना चाहिए।

bjpkamaljyoti@gmail.com

एक भारत, श्रेष्ठ भारत का आधार सांस्कृतिक एकता

राजकुमार

काशी को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी, बाबा भोले नाथ का निवास कहाँ गया है, सर्व विद्या की, राजधानी मानी जाती है भारत के सभी प्रदेशों के भाषा भाषी यहाँ निवास करते हैं काशी भारतीय सांस्कृतिक एकता का सूत्रधार मानी जाती है ऐसे में ''काशी तमिल संगमम्'' भारतीय एकात्मता को मजबूत किया ज्ञान, कला, खेल, गीत, संगीत के अनेकों प्रकार के आयोजन हुए। आजादी के बाद एक समय ऐसा आया, जब देश की सांस्कृतिक एकता में जहर घोलने का प्रयास किया गया। लेकिन अब समय आ गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना करने का और वो भारत की सांस्कृतिक एकता से ही हो सकता है। यह कहना है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का। उत्तर–दक्षिण भारत के रिश्ते की प्रगाढ़ता के लिए खास आयोजन काशी–तमिल संगमम के समापन समारोह में गृहमंत्री शामिल हुए। बीएचयू के एंफीथिएटर मैदान में आयोजित भव्य समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि लंबे समय से हमारे देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था।

आजादी के बाद देश की सांस्कृतिक एकता में जहर घोलने का प्रयास किया गया था: अमित शाह

प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम के माध्यम से सदियों बाद ये प्रयास किया है। ये प्रयास पूरे देश की भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का सफल प्रयास सिद्ध होगा। गृहमंत्री ने कहा कि आज मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि विश्वास और प्रेम में एक समानता यह है कि दोनों को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। काशी तमिल संगमम ने आजादी के अमृतकाल वर्ष में उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों के बीच विश्वास और प्रेम का नया माहौल खड़ा करने का काम किया है।

गुलामी के एक लंबे काल खंड में हमारी संस्कृति और विरासत को मलिन करने का प्रयास किया गया है। हमें आनंद है कि भारत की आजादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम किया है। मैं इसके लिए उन्हें बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूं।

भारत अनेक संस्कृतियों, भाषाओं, बोलियों और कलाओं से बना हुआ देश है। मगर, इन सबके बीच में बारीकी से देखें तो उसकी आत्मा एक है और वह भारत की आत्मा है। दुनिया के अन्य देश जिओ पॉलिटिकल आधार बने हुए हैं, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना काशी तमिल संगमम की पूर्णाहुति होने जा रही है। मगर, यह पूर्णाहुति नहीं शुरुआत है। यह तमिलनाडु और काशी की महान संस्कृति, कला, दर्शन, ज्ञान के मिलन की शुरुआत है। यह प्रयास आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, लेकिन काफी साल तक नहीं हुआ

तमिलनाडु से आए भाई–बहन काशी

से गंगाजल ले जाकर रामेश्वरम में अभिषेक कीजिएगा। फिर जब वहां से आइएगा तो वहां की मिट्टी लाकर गंगा के रेत में मिलाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी व्यवस्था की है कि पूरे देश को जानिए और समझिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार कीजिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु भारत की कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं, इसके साथ ही दोनों प्रदेश भारत में एमएसएमई के सबसे बड़े सेंटर भी हैं। इन दोनों प्रदेशों की सांस्कृतिक

विचारधाराओं के संगम से ना सिर्फ समृद्धि के द्वार खुलेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प भी साकार होगा।

काशी तमिल संगमम के समापन समारोह को वणक्कम काशी और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ संबोधित करते हुये योगी ने कहा '' काशी, प्रयाग और अयोध्या यात्रा की मधुर स्मृतियों को आप सब तमिलनाडु के घर घर तक पहुंचाएंगे। साथ ही तमिलनाडु के लोगों को यूपी आने के लिए प्रेरित करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है।'' उन्होंने कहा कि तमिल कार्तिक मास से काशी तमिल संगमम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान शिव की इस पवित्र भूमि पर किया था। बीते एक माह में तमिलनाडु से 12 अलग–अलग ग्रुपों ने यहां आकर दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का कार्य किया है।

यूपी और तमिलनाडु के बीच की प्राचीन समानताओं को भी अनुभव

मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु से आए सभी 12 समूहों ने काशी के साथ ही प्रयाग और अयोध्या जाकर यूपी और तमिलनाडु के बीच की प्राचीन समानताओं को भी अनुभव किया है। इसका संदेश ना केवल उत्तर प्रदेश में सकारात्मक रूप से गया है, बल्कि तमिल अतिथियों ने बहुत नजदीक से उत्तर प्रदेश की संस्कृति को अनुभव किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते एक माह में यहां आए समूहों में बहुत से ऐसे लोग भी शमिल थे जो पहली बार काशी, प्रयाग और अयोध्या पहुंचे थे। ये कार्यक्रम बहुत कुछ कह रहा है।

उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु भारत की आध्यात्मिक संस्कृति, कला, शिल्प और साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों के संगम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना साकार होती है। ये अछ्वुत और अविस्मरीणय है। दोनों प्रदेशों में एक और समानता दिखती है। दोंनों ही भारत में एमएसएमई के सबसे बड़े केंद्र हैं। इन दोनों के बीच की समानता आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी साकार करती है।

काशी विश्वनाथ धाम और रामनाथ स्वामी रामेश्वरम दोनों ही पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं। इन दोनों से जुड़ी संस्कृतियों का यह परस्पर मेल मिलाप निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप अपनी इस यात्रा की मधुर स्मृतियों को तमिलनाडु के हर घर तक पहुंचाएंगे और उन्हें यूपी आने के लिए प्रेरित करेंगे।

पाकिस्तान की पहचान आतंकवाद

पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के शर्मनाक बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। राजधानी लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यालय से अटल चौक तक विरोध मार्च निकालकर बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया। भाजपा ने जिला स्तर पर भी जोरदार प्रदर्शन कर पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान का विरोध करते हुए पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन पार्टी पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए।

मुख्यालय पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान की भर्त्सना की। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का बयान उनकी कुंठा और मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है। आज विश्व पटल पर पाकिस्तान की पहचान आतंकवाद को पालने–पोसने और बढ़ावा देने वाले देश की बन गई है। पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री चलती है। पाकिस्तान के आंतरिक हालात और उसकी बदहाली किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान के लगातार बिगड़ते आर्थिक हालात, सेना का मनमुटाव दुनिया भर के देशों से पाकिस्तान के खराब रिश्ते और आतंक को संरक्षण की पाकिस्तानी नीति से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ऐसा गिरा हुआ और अमर्यादित बयान दिया है।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बनी है। भारत की विदेश नीति की सराहना चहुओर हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान–सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री पर अमर्यादित बयान देकर पाकिस्तान पर एक कलंक और लगाया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में मेरठ, आगरा, गोरखपुर, काशी, कानपुर, अयोध्या, देवरिया, बरेली सहित कई स्थानों पर नगर, बूथ की इकाईयों ने जोरदार प्रदर्शन किये।

नव्य दिव्य भारत बनाने का संकल्प!

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोगों ने अगले 25 वर्षों के अमृत काल के दौरान ने एक गौरवशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। सरकार की भूमिका लोगों के प्रयासों में सक्षमकर्ता बनकर उनके संकल्प को पूरा करने में सहायता करने की है। हमारी भूमिका अवसरों को बढ़ाने और उनके मार्ग से बाधाओं को दूर करने की है।

19–25 दिसंबर, 2022 तक मनाए जा रहे दूसरे "सुशासन सप्ताह" की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने एक संदेश में कहा, 'नागरिक–प्रथम' के सिद्धांत द्वारा निर्देशित, हमारी सरकार हर स्तर पर प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों को सरल बनाकर इकोसिस्टम को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा, हमने सार्वजनिक शिकायतों के निवारण, ऑनलाइन सेवाओं, सेवा प्रदायगी अनुप्रयोगों के निपटान और सुशासन प्रथाओं सहित विभिन्न नागरिक केंद्रित पहल की शुरुआत की है। हमारा विजन सेवा प्रदायगी तंत्र की पहुंच का विस्तार करना है, जिससे उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

लोगों ने अगले 25 वर्षों के अमृत काल में एक गौरवशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है और सरकार की भूमिका लोगों के प्रयासों में सक्षमकर्ता बनकर उनके संकल्प में सहायता करनी है।

प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा सदैव प्रयास रहा है कि शासन का प्रभाव बढ़े, लेकिन प्रत्येक नागरिक के जीवन में सरकार का हस्तक्षेप कम हो। हजारों अनावश्यक अनुपालनों को खत्म करना, हजारों पुराने कानूनों को निरस्त करना और कई तरह के गौण अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना इस दिशा में प्रमुख कदम है।

प्रधानमंत्री ने कहा, प्रौद्योगिकी में सरकार और नागरिकों को निकट लाने की प्रचुर क्षमता है। आज, प्रौद्योगिकी नागरिकों को सशक्त बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण बन गई है, साथ ही दिन–प्रतिदिन के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को इष्टतम बनाने का एक माध्यम भी बन गई है। विभिन्न नीतिगत युक्तियों के माध्यम से हम नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण और संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, यह विशेष रूप से प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष भी 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान सुशासन सप्ताह का हिस्सा बना हुआ है और उन्होंने इस पहल से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दीं।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 19 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और सुशासन सप्ताह समारोहों के हिस्से के रूप में देश भर में 'प्रशासन गांव की ओर' 2022 अभियान की शुरुआत करेंगे।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), 19 से 25 दिसंबर 2022 के दौरान सुशासन सप्ताह मना रहा है। सप्ताह के दौरान, डीएआरपीजी राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में सुशासन सप्ताह 'प्रशासन गांव की ओर' 2022 का आयोजन कर रहा है। इस अभियान में भारत के सभी तहसीलों/जिलों में सेवा प्रदायगी में सुधार लाने और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और प्रगति की रिपोर्ट जिला कलेक्टरों द्वारा एक समर्पित अभियान पोर्टल पर की जाएगी।

डॉ. सिंह सुशासन प्रथाओं पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे और जिला कलेक्टरों और राज्य सरकारों द्वारा प्रगति के ऑनलाइन अद्यतन के लिए **'प्रशासन गांव की ओर'** 2022 के लिए समर्पित अभियान पोर्टल लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर "प्रशासन गांव की ओर" पर एक फिल्म दिखाई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव और कर्नाटक, एआर के प्रधान सचिव, अपने–अपने राज्यों में सुशासन पहलों पर प्रस्तुति देंगे।

'प्रशासन गांव की ओर' 2022 लोक शिकायतों के निवारण और सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान होगा जो भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। 700 से अधिक जिला कलेक्टर प्रशासन गाँव की ओर 2022 में हिस्सा लेंगे। लोगों की शिकायतों को दूर करने और बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए जिला कलेक्टर तहसील /पंचायत समिति मुख्यालय आदि में विशेष शिविर/कार्यक्रम आयोजित करेंगे। नागरिकों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले निम्नलिखित मुद्दों पर

ध्यान केन्द्रित करते हुए अभियान चलाया जाएगा:

- सीपीजीआरएएमएस में लंबित लोक शिकायतों का निवारण
- राज्य पोर्टलों में जन शिकायतों का निवारण
- ऑनलाइन सेवा प्रदायगी के लिए जोड़ी गई सेवाओं की संख्या
- सेवा प्रदायगी आवेदनों का निपटान
- सुशासन प्रथाओं का मिलान और उनका प्रसार
- लोक शिकायतों के समाधान पर प्रत्येक जिले में एक सफलता गाथा साझा करना

'प्रशासन गांव की ओर' 2022 - 19 से 25 दिसंबर, 2022 तक सुशासन सप्ताह के दौरान लोक शिकायतों के निवारण और सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान

सुशासन सप्ताह के दौरान, 23 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सुशासन प्रथाओं पर एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें कैबिनेट सचिव मुख्य अतिथि होंगे। विशेष अभियान 2.0 और निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। डाक विभाग के सचिव; रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष; भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक विशेष अभियान 2.0 के दौरान अपने विभागों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रस्तुतीकरण देंगे। एनआईसी के महानिदेशक; विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व), और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, 'निर्णय लेने में बढ़ती दक्षता' पर प्रस्तुतियां देंगे। इस कार्यशाला में विशेष अभियान 2.0 आकलन रिपोर्ट जारी की जाएगी।

प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने के लिए इस वर्ष के 'प्रशासन गांव की ओर' 2022 अभियान में एक नवोन्मेषी विशेषता जोड़ी गई है। देश के सभी जिले 23 दिसंबर, 2022 को "सुशासन प्रथाओं/पहलों" पर एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे, जिसे 'प्रशासन गांव की ओर पोर्टल' पर कार्यशाला के चित्रों के साथ मिलान तथा साझा किया जाएगा। जिला/2047 अर्थात जिला/100 के विजन के साथ जिन प्रमुख क्षेत्रों में जिले में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, उन्हें कार्यशाला में रेखांकित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में जिले के एक सेवानिवृत्त डीसी/डीएम को आमंत्रित किया जाएगा और जिला स्तरीय कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सभी विभागों, शिक्षाविदों और प्रमुख शिक्षण संस्थानों के थिंक टैंक के जिला स्तरीय अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। ये कार्यशालाएं जमीनी स्तर पर सुशासन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और प्रलेखन के लिए एक मंच होंगी और जिला/100 के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट की रूपरेखा तैयार करेंगी।

वर्ष 2021 में 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान के दौरान, सेवा प्रदायगी के लिए 2.89 करोड़ से अधिक आवेदनों का निपटान किया गया, 6.5 लाख से अधिक शिकायतों पर ध्यान दिया गया, 621 सेवाओं को सिटीजन चार्टर्स में जोड़ा गया, 380 सिटीजन चार्टर्स का अद्यतन किया गया, 265 सर्वोत्तम शासन पद्धतियां और 236 सफलता गाथाएं पोर्टल पर अपलोड की गईं।

'प्रशासन गांव की ओर' 2022 अभियान के जिला स्तर पर और भी अधिक उत्साह से आगे बढ़ाने जाने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य भारत के सभी जिलों और तहसीलों के नागरिकों को प्रशासन के करीब लाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को साकार करना है। सुशासन सप्ताह के दौरान 'प्रशासन गांव की ओर' 2022 अभियान शासन के नागरिक–केंद्रित दृष्टिकोण की दिशा में पहल को आगे बढ़ाने के लिए सुशासन के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन का सृजन करेगा।

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें और जिले अभियान, उद्घाटन कार्यक्रम और कार्यशालाओं में हिस्सा लेंगे

एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य

प्रो0 रसाल सिंह

भारत ने 1 दिसंबर, 2022 को आगामी वर्ष के लिए बीस देशों के शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय समूह जी–20 का अध्यक्षीय पद ग्रहण किया है। हाल ही में संपन्न 'बाली शिखर सम्मेलन' में पूर्व अध्यक्ष देश इंडोनेशिया द्वारा वर्ष 2023 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। जी–20 समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 80%, वैश्विक व्यापार के 75% और वैश्विक आबादी के 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के लिए जी–20 एक अनूठी वैश्विक संस्था है, जहां विकसित और विकासशील देशों का समान महत्व है। यहां विकासशील देश सबसे शक्तिशाली देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक नेतृत्व को प्रदर्शित कर सकते हैं। भारत का दुनिया के सबसे प्रभावशाली बहुपक्षीय समूह का नेतृत्व करना हर्षोल्लास का विषय है, जिसे भारत के बढ़ते वैश्विक राजनीतिक कद और प्रतिष्ठा के रूप में देखा जा सकता है। यह उत्तर–दक्षिण के आर्थिक विभाजन और दूरी को कम करने में सक्षम है। भारत के लिए वह बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है,जब वार्ता की मेज से वह अपनी पहली वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका में नई नीतियों के क्रियान्वयन का नेतृत्व करेगा। यह निर्णय हरित निवेश को सुनिश्चित करने और 'ग्लोबल साउथ' समूह जिसमें बड़े पैमाने पर लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया जैसे निम्न–आय वाले देश शामिल हैं, इनके लाभ के लिए विकसित देशों को सहमत करने की कोशिश करता है। भारत कमजोर देशों की सहायता करने, विकासशील देशों के लोगों की आकांक्षाओं को मुखरित करने और उनके मुद्दों को केंद्र में लाने के लिए जी–20 की प्रमुख भूमिका पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करने के लिए तत्पर है, क्योंकि उनमें से अधिकांश देशों का जी–20 में प्रतिनिधित्व नहीं है।

भारत के पास इस अध्यक्षीय पद का कार्यभार भू–राजनीतिक उथल–पुथल, महामारी के बाद की आर्थिक अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन के उभरते संकट के समय में आया है। रूस–यूक्रेन संघर्ष ने रूस और औद्योगिक रूप से विकसित पश्चिमी देशों के बीच संबंध खराब कर दिए हैं। इनमें से अधिकांश जी–20 के सदस्य हैं। जहाँ सशस्त्र संघर्ष और पश्चिम द्वारा लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों ने महामारी के बाद वैश्विक विकास को बाधित किया है, वहीं तेल व गैस की कीमतों तथा भोजन की उपलब्धता पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। बढ़ती बेरोज़गारी और महंगाई का असर सबसे पहले कमजोर एवं विकासशील देशों ने महसूस किया है। विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक विकास दर 2021 में 5.5% से 2022 में 4.1% और 2023 में 3.2% तक गिरने की संभावना है, क्योंकि बैकलॉग डिमांड फ्रिक्टर्स और राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन दुनिया भर में विभाजित हैं। कोविड–19 महामारी और रूस–यूक्रेन संघर्ष के झटकों से निपटने में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण भारत एक अन्यथा अंधेरे और उदासीन वैश्विक परिदृश्य में आशा की किरण के रूप में उभरा है। इसके अलावा एक सभ्यता के रूप में भारत 'विविधता में एकता' की परंपरा पर गर्व करता है जिसे कई उप–संस्कृतियों के सामरस्य द्वारा सदियों से पोषित किया जाता रहा है। पिछले 75 वर्षों में भारत ने सभी नागरिकों को समायोजित करने और मतभेदों के बीच फलने–फूलने की अविश्वसनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। 'विविधता में एकता' की कहावत भारत के लिए विषमताओं के बावजूद भी सच है। भारत आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल के तौर पर उभरा है। यदि बहुपक्षवाद को सफल होना है, तो जी–20 के सदस्य देशों को भारत के तरीके से काम करना चाहिए और एक दूसरे के साथ बातचीत को बढ़ाना चाहिए। दुनिया जी–20 देशों और उनके अध्यक्ष भारत की ओर देख रही है ताकि अवशोषक के साथ–साथ मध्यम और दीर्घकालिक समाधानों पर विचार की कोशिश की जा सके।

2023 में जी–20 सम्मेलन की अध्यक्षता करना भारत के लिए सम्भावनापूर्ण चुनौती है। भारत को अपने वैचारिक नेतृत्व की भूमिका द्वारा वैश्विक ध्रुवीकरण को कम करने के व्यापक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए जी–20 अध्यक्ष पद का उपयोग करना चाहिए। संसाधनों को समावेशी तरीके से संयोजित करना चाहिए और विकासात्मक प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। भारत विश्व के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत द्वारा अध्यक्षता के लिए निर्धारित नारा "एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य" है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत लगभग 50 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित करेगा जिसमें मंत्री, अधिकारी और नागरिक शामिल होंगे। यह कार्यकाल सितंबर 2023 में राजधानी नई दिल्ली में एक प्रमुख शिखर सम्मेलन के साथ पूरा होगा। शिखर सम्मेलन में जी–20 सदस्यों और आमंत्रित देशों से लगभग 30 प्रमुख लोग भाग लेंगे। इस सम्मेलन में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए एकता और सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा की उम्मीद है।

एक प्रमुख अर्थव्यवस्था और एक विकसित लोकतंत्र और विकासशील देश होने के नाते भारत के पास न्यायसंगत, हरित और लचीले आर्थिक सुधारों पर ध्यान देने के साथ 'एजेंडा–2023' निर्धारित करने का अनूठा अवसर है। अपनी स्वतंत्रता के 76वें वर्ष में भारत 2023 के लिए वैश्विक आर्थिक

शासन का एजेंडा निर्धारित करेगा और विश्व के अंतरराष्ट्रीय नीति संवाद को आकार देने के साथ अपनी वैश्विक आकांक्षाओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को रेखांकित करने की पहल करेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार जी–20 अध्यक्षता के तहत भारत निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा हैः "महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, जलवायु वित्तपोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, हरित हाइड्रोजन, आपदा जोखिम, आर्थिक अपराध के खिलाफ लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार। एजेंडे को करीब से देखते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की अध्यक्षता मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र में जलवायु सहजीवन, ऊर्जा सुरक्षा और हरित हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करेगी। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने दोहराया कि विकसित दुनिया ने जलवायु पर सीमित कार्रवाई की है, जिसमें जलवायु वित्त भी शामिल है, जो भारत की जी–20 अध्यक्षता के दौरान एक प्रमुख चर्चा का बिंदु होगा। इसके अलावा भारत को ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान–प्रदान, मानकीकरण और ऊर्जा क्षेत्र में राजनीतिक मध्यस्थता के बारे में चर्चा करनी चाहिए।

भारत 2020 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 उच्च प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल है, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े प्रदूषक सूची में बहुत नीचे हैं। जलवायु परिवर्तन और कार्य योजना का मुद्दा जी–20 और भारत के रिश्ते को और मजबूत करेगा। भारत जलवायु और विकास एजेंडे को एकीकृत करने और एसडीजी 2030 जनादेश को प्राप्त करने की दिशा में तेजी लाने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिणाम देने का प्रयास करेगा। सतत विकास की खोज मौलिक है। इस दिशा में भारत द्वारा 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन कम करना और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत पूरा करने का संकल्प स्वागत योग्य है। भारत जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रों में अपनी पहुंच और क्षमता को भी बढ़ावा देना चाहेगा। जैसा कि अंतरराष्ट्रीय सौर समूहों और आपदा जोखिम पहल परियोजनाओं में परिकल्पित है। जी–20 के अध्यक्ष के रूप में भारत स्पष्ट रूप से पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी के प्रावधान के प्रमुख समर्थक के रूप में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रचारित 'स्थिरता' का मंत्र जी–20 घोषणा में चर्चित संयमित खपत और जिम्मेदार उत्पादन पैटर्न में परिलक्षित होता है। हाल ही में संपन्न ब्व्27 ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सीमित संसाधनों वाले कमजोर देशों का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से 'नुकसान और क्षति कोष' की घोषणा की थी। इसे आगे बढ़ाते हुए भारत की अध्यक्षता में स्वच्छ अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए अधिक प्रभावी आर्थिक लक्ष्यीकरण पर जी–20 में फिर से पुष्टि होने की उम्मीद है।

भारत के पास इन परिवर्तनों के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और हरित ऊर्जा और डिजिटलकरण को प्रोत्साहित करने के पक्ष में वैश्विक आख्यान को आकार देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिनका उद्देश्य 500 गीगावाट की गैर–जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का उत्पादन और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत बिजली आवश्यकताओं को पूरा करना है। अपने स्वदेशी परमाणु बिजली कार्यक्रम का निरंतर विस्तार और बिजली उत्पादन के लिए सौर व पवन ऊर्जा के उपयोग की दिशा में निरंतर तेजी, इसी दिशा में बढ़ते कदम हैं। आज की ध्रुवीकृत दुनिया में साझेदारी और दोस्ती बढ़ाने की भारत की क्षमता ऊर्जा आबंटन के मुद्दों को ध्यान में लाने में मदद कर सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विचार किस प्रकार से कार्यान्वित होते हैं और अंततः दुनिया को कैसे प्रभावित करते हैं। नई दिल्ली के संरक्षण और जिम्मेदार खपत के पारंपरिक दृष्टिकोण को जी–20 की अध्यक्षता के दौरान सादगीपूर्ण जीवन शैली को उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने भी ग्लासगो, 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) के दौरान LIFE (Lifestyle For Environment) अर्थात "पर्यावरण के लिए जीवन शैली" के अपने आह्वान के साथ ही सभी नागरिकों को इस रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया था। भारत की जी–20 की अध्यक्षता जलवायु स्थिरता पर घरेलू और वैश्विक पहल शुरू कर ऊर्जा आबंटन के एजेंडे और उसके ज़मीनी कार्यान्वयन में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत सार्वजनिक निजी भागीदारी के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया का दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है जो स्थिर और समावेशी विकास का समर्थन करने के लिए जी–20 में सार्थक योगदान देगा। जी–20 की अध्यक्षता भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगी और भारत को अपनी प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी। यह उसकी प्रगति और विकास के साथ–साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को प्रदर्शित करने का भी एक अनूठा अवसर होगा। भारत की जी–20 की अध्यक्षता जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद है। भारत के बढ़ते वैश्विक वर्चस्व के कारण अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसकी भूमिका और वैश्विक संकटों/चिंताओं पर इसकी प्रतिक्रिया यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी को और भी सुदृढ़ करेगी। जहां भारत को जलवायु व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, वहीं दुनिया अब भारत की रणनीतिक और नेतृत्वकारी पहलों को देखने, सुनने और उनका पालन करने के लिए तैयार है। विश्व में वैचारिक और संवादधर्मी नेतृत्व का जो रिक्त है उसे भरने का भारत के पास सुनहरा अवसर है।

हर बूथ - हर घर भाजपा : भूपेन्द्र

प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि निकायों में किए गए विकास कार्यों के साथ ही मोदी सरकार व योगी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, नगरीय परिवहन, मेट्रो रेल सेवा, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना तथा अमृत मिशन जैसी योजनाओं बदली नगर निकायों की स्थिति भाजपा की बड़ी विजय का आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के परिश्रमी कार्यकर्ताओं का जनता के साथ सतत सम्पर्क व संवाद ही पार्टी को सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही व सर्वसमावेशी बनाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश से लेकर बूथ तक के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव में पार्टी की जीत के लिए काम करना है। उन्होंने जिला व वार्ड स्तर पर चुनाव समितियों के गठन पर भी जोर दिया। श्री चौधरी ने कहा कि एक–एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपकर चुनावी रणनीति तैयार की जाए। हर बूथ भाजपा–हर घर भाजपा के मंत्र के साथ प्रत्येक दहलीज तक सम्पर्क करना है।

राज्य मुख्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता व प्रदेश महामंत्री संगठन श्री धर्मपाल सिंह जी की मौजूदगी में हुई बैठक में पार्टी के प्रदेश महामंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष, नगर निगमों में निकायों के संयोजक और मोर्चो के प्रदेश अध्यक्ष सम्मिलित हुए। बैठक में पार्टी द्वारा विगत दिनों चलाए गए कार्यक्रमों व अभियानों की समीक्षा की गई साथ ही आगामी कार्यक्रमों की योजना बनी।

मण्डल प्रवास योजना के तहत प्रदेश से लेकर जिले तक का प्रत्येक पदाधिकारी मण्डलों में प्रवास करने जायेगें। मण्डल प्रवासी मण्डलों में जाकर मण्डल के पदाधिकारियों, सेक्टर व बूथ के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ संगठनात्मक बैठकें करेंगे। प्रवास के दौरान लोगों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की केन्द्र सरकार व मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की प्रदेश भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों, ऐतिहासिक निर्णयों तथा पार्टी की विचारधारा पर चर्चा करेंगे।

प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह ने बैठक में कहा कि बूथ की मजबूत संरचना ही संगठन की मजबूती का आधार है। इसलिए बूथ सशक्तिकरण के लिए हम सभी को जुटना है। बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम, अभियान व योजना के केन्द्र में सेक्टर व बूथ ही होना चाहिए। हमें सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुना जाए। बूथ पर नियमित बैठकें हो तथा बूथ समिति के एक–एक सदस्य की संगठनात्मक जिम्मेदारी तय हो। बूथ समितियों के साथ पन्ना प्रमुखों का सम्पर्क व संगठन द्वारा तय कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए पन्ना प्रमुखों का पन्ने पर अंकित सभी मतदाताओं से नियमित सम्पर्क तय किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा–बसपा समेत तमाम विपक्षी दल सिर्फ चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं। जबकि भाजपा अनवरत रूप से प्रकृति संरक्षण संवर्धन, जनसेवा तथा अन्य सामाजिक सरोकार के कार्यों के द्वारा जनता के बीच रहती है। जनता के बीच यही सतत सक्रियता भाजपा को जन–जन की पार्टी बनाती है। उन्होंने मोर्चो के कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ आगामी कार्ययोजना पर कहा कि सभी मोर्चे आगामी दिनों में सेक्टर व बूथ स्तर पर अपनी सक्रियता को और अधिक बढ़ाते हुए अधिक से अधिक लोगों को पार्टी विचारधारा के साथ जोड़े।

बैठक में प्रदेश महामंत्री श्री जे0पी0एस राठौर, श्री गोविन्द नारायण शुक्ला, श्री अश्वनी त्यागी, श्री अमर पाल मौर्य, श्री अनूप गुप्ता, श्रीमती प्रियंका सिंह रावत, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेन्द्र सिंह, डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह, श्री मोहित बेनिवाल, श्री रजनीकान्त महेश्वरी, श्री महेश चन्द्र श्रीवास्तव सहित मोर्चो के प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री सम्मिलित रहे।

भारतीय मूल्यों के प्रकाश में विकास

श्री ललित गर्ग

भारत दुनिया की एक उभरती हुई सशक्त आर्थिक व्यवस्था है, विकास के नये आयाम उद्घाटित करते हुए भारत ने दुनिया को चौंकाया है, अचंभित किया है। भारत की विकास अवधारणा न केवल आर्थिक संवृद्धि से जुड़ी है, अपितु यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया है जो लोगों को जीवन की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए अभिप्रेरित करती है और विकास प्रक्रिया में उन्हें सहभागी बनाती है। यह विकास अंततः आत्मनिर्भरता, समानता, न्याय एवं संसाधनों का एकसमान वितरण को बल देती है जो राष्ट्रीयता एवं लोकतंत्र की मजबूती का भी आधार है। भारत के वर्तमान विकास को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत निरंतर जागरूक है एवं अपने विचारों से यह विकास कहीं भटक न जाये, उसके लिये चेताते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने मुम्बई में यह बयान देकर भारत के जन—जन को अभिप्रेरित किया है कि इस देश का विकास अमेरिका या चीन की तर्ज पर नहीं हो सकता बल्कि इसका विकास भारतीय दर्शन और इसकी संस्कृति तथा सकल संसार के बारे में इसके सुस्थापित विचारों के अनुरूप ही किया जा सकता है। देश के विकास की प्राथमिक आवश्यकता है कि गरीब का संबोधन मिटे। गरीबी एवं अमीरी के बीच का दूरियों को समाप्त किया जाये। प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े। संघ एक समतामूलक संतुलित समाज व्यवस्था का पोषक है। तभी वह गांव का विकास चाहता हैं और तभी ग्राम आधारित अर्थ—व्यवस्था को विकसित होते हुए देखना चाहता है।

संघ प्रमुख भागवत ऐसे ही विकास को चाहते हैं और मुंबई में उनके इन्हीं विचारों में ऐसी ही रोशनी प्रकट भी हुई है। उनके विचारों में जहां विवेकानन्द का दर्शन है वहीं गांधीवाद भी समाया है। उनके विचार उन आर्थिक सिद्धान्तों से उपजा है जिनके बारे में राष्ट्रपति महात्मा गांधी जीवनभर समर्पित थे और ग्रामों के विकास को ही भारत के सर्वांगीण विकास का फार्मूला मानते थे। उनका विकास मन्त्र पाश्चात्य विकास सिद्धान्त से पूरी तरह भिन्न था और वह मानते थे कि गांवों के आत्मनिर्भर होने से भारत में आत्मनिर्भरता आयेगी। इसका मतलब यह कदापि नहीं था कि गांव व ग्रामीण जगत आधुनिक विकास प्रणाली से विमुख रहेगा बल्कि यह था कि औद्योगीकरण का पहिया गांवों से शहरों की तरफ धूमेगा तभी देश का समुचित और सम्यक विकास संभव होगा तथा गरीबी का प्रवाह रुकेगा।

गांवों के विकास को गति देकर ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। अब तक की विकास अवधारणा में गरीबी की रेखा का महिमामंडन बहुत हुआ है। गरीबी की रेखा क्या? क्यों है? किसने खींची यह लक्ष्मण रेखा, जिसको कोई पार नहीं कर सकता। जिस पर सामाजिक व्यवस्था चलती है, जिस पर राजनीति चलती है, जिसको भाग्य और कर्म की रेखा मानकर उपदेश चलते हैं। वस्तुतः ये रेखाएं तथाकथित गरीबों ने नहीं खींचीं। आप सोचिए, भला कौन दिखायेगा अपनी जांघ। यह रेखाएं अमेरिकी एवं चीनीवादी सोच ने खींची हैं जो अपनी जांघ ढकी रहने देना चाहते हैं। इस रेखा (दीवार) में खिड़कियां हैं, ईर्ष्या की, दम्भ की। पर दरवाजे नहीं हैं इसके पार जाने के लिए। एक आजाद मुल्क में, एक शोषणविहीन समाज में, एक समतावादी दृष्टिकोण में और एक कल्याणकारी समाजवादी व्यवस्था में यह रेखा नहीं होनी चाहिए। यह रेखा उन कर्णधारों के लिए "शर्म की रेखा" है, जिसको देखकर उन्हें शर्म आनी चाहिए। गांधी ने इसी रेखा को दूर करने का दर्शन दिया और अब भागवत उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं।

भारत की वर्तमान विकास प्रक्रिया में अनेक चिन्तन के बिन्दू है कि जो रोटी नहीं दे सके वह सरकार कैसी? जो अभय नहीं बना सके, वह व्यवस्था कैसी? जो इज्जत व स्नेह नहीं दे सके, वह समाज कैसा? जो शिष्य को अच्छे—बुरे का भेद न बता सके, वह गुरु कैसा? अगर तटस्थ दृष्टि से बिना रंगीन चश्मा लगाए देखें तो हम सब गरीब हैं। गरीब, यानि जो होना चाहिए, वह नहीं हैं। जो प्राप्त करना चाहिए, वह प्राप्त नहीं है। चाहे हम अज्ञानी हैं, चाहे भयभीत हैं, चाहे लालची हैं, चाहे निराश हैं। हर दृष्टि से हम गरीब हैं। जैसे भय केवल मृत्यु में ही नहीं, जीवन में भी है। ठीक उसी

प्रकार भय केवल गरीबी में ही नहीं, अमीरी में भी है। यह भय है आतंक मचाने वालों से, सत्ता का दुरुपयोग करने वालों से जहां है वहां से नीचे उतर जाने का, प्रियजनों की सुरक्षा का। जब चारों तरफ अच्छे की उम्मीद नजर नहीं आती, तब मनुष्य नैतिकता की ओर मुड़ता है। यह वह सशक्त मोड़ है जो शर्म की रेखा को तोड़ने के लिए यत्न करता है। शर्मी और बेशर्मी दोनों मिटें। गरीबी का संबोधन मिटे। तब हम सूर्योदय के नजदीक होंगे। ऐसा सूर्योदय न तो चीन का अनुसरण करने से आयेगा और अमेरिका का। यह भारतीय दर्शन को, यहां की संस्कृति को मजबूती देकर ही आ सकेगा।

भागवत भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता है, भाष्यकार है, वे जितने दार्शनिक है, उतने ही व्यावहारिक भी हैं। सांस्कृतिक उत्थान के साथ वे स्वस्थ समाज निर्माण के सूत्रधार भी हैं। वे ऐसे धार्मिक हैं जिनका प्राथमिक धर्म राष्ट्रीयता है। तभी श्री भागवत ने कहा कि जो धर्म मनुष्य को सुविधा सम्पन्न और सुखासीन बनाता है मगर प्रकृति को नष्ट करता है, वह धर्म नहीं है। यहां धर्म का अर्थ मजहब नहीं बल्कि कर्त्तव्य या इंसानियत है। उपभोग एवं सुविधावादी धर्म की जड़ 'पाश्चात्य की उपभोग' संस्कृति में बसी हुई है। जबकि भारत की मान्यता 'उपयोग' की रही है, त्याग की रही है। इस बारे में भी महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में प्रत्येक रईस या सम्पन्न व्यक्ति को अपने उपभोग की अधिकतम सीमा तय करनी चाहिए और शेष सम्पत्ति को समाज के उत्थान मूलक कार्यों में लगाना चाहिए। वास्तव में यही गांधी का 'अहिंसक समाजवाद' था और ऐसा ही उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त था। इसी समाजवाद की स्थापना संघ का ध्येय है।

भारतीय संस्कृति में भौतिक सुख का अर्थ यह कदापि नहीं बताया गया कि व्यक्ति पूर्णतः स्वार्थी होकर समाज, संस्कृति और दैवीय उपकारों की उपेक्षा करने लगे बल्कि यहां 'दरिद्र नारायण' की सेवा को ईश्वर भक्ति का साधन माना गया।

प्रकृति का विनाश करके विकास खोजने वाले राष्ट्र भारत के आदर्श नहीं हो सकते। कोरोना जैसी महाव्याधियों को पैदा करने वालों को हम आदर्श मान भी नहीं सकते। क्योंकि कोरोना महामारी प्रकृति की उपेक्षा का ही परिणाम है। चीन व अमेरिका जैसे देशों में प्रकृति को बेजान मानते हुए उसकी कीमत पर किये गये विकास को उपलब्धि मान लिया गया है। चीन में तो विकास का पैमाना अमेरिका से भी और ज्यादा विद्रूप एवं त्रासद है क्योंकि इस देश की 'कम्युनिस्ट पूंजीवादी' सरकार ने मनुष्य को ही 'मशीन' में तब्दील कर डाला है जिसकी वजह से मनुष्य की संवेदनाएं भी मशीनी हो गई हैं। भारतीय संस्कृति में भौतिक सुख का अर्थ यह कदापि नहीं बताया गया कि व्यक्ति पूर्णतः स्वार्थी होकर समाज, संस्कृति और दैवीय उपकारों की उपेक्षा करने लगे बल्कि यहां 'दरिद्र नारायण' की सेवा को ईश्वर भक्ति का साधन माना गया। जब हम प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं तो इसमें सम्पत्ति के समुचित बंटवारे का भाव भी समाहित रहता है क्योंकि भारत में प्राकृतिक सम्पदा पर आश्रित रहने वाला पूरा समाज अपने आर्थिक विकास के लिए इसी पर निर्भर रहता है। बड़े कल कारखाने निश्चित रूप से विकास की आवश्यक शर्त होते हैं और भौतिक सुख–सुविधा प्राप्त करने का अधिकार भी बदलते समय के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का होता है परन्तु यह दूसरे व्यक्ति को उजाड़ कर पूरा नहीं किया जा सकता।

संघ एवं संघ प्रमुख ने समय–समय पर सरकार को 'भारतीय मूल्यों के प्रकाश में' विकास की अवधारणा देने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब संघ के मौजूदा आर्थिक दर्शन एवं विकास की अवधारणा को भारतीय विशेषताओं के साथ लोकप्रियता के रूप में अच्छी तरह से समझा जा सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अप्रैल, 2018 में मुंबई के आभिजात्य व्यवसायी वर्ग को संबोधित करते हुए भागवत ने संघ के आर्थिक दर्शन की स्पष्ट घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि संघ किसी आर्थिक वाद से जुड़ा नहीं है और आर्थिक नीति की जांच करने के लिए कसौटी यह होनी चाहिए कि इसका लाभ गरीबों तक पहुंचेगा या नहीं। स्पष्ट है कि संघ भारत का विकास मूल्यों एवं नैतिक अवधारणाओं पर होते हुए देखना चाहता है। जीवित रहना जीवन का लक्ष्य नहीं है। सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना ही वह काम है, जो जानवर भी करते हैं। शक्तिशाली ही जीवित रहेगा, यह जंगल का कानून है। योग्यतम की उत्तरजीविता ही जंगल पर लागू होने वाला सत्य है जबकि दूसरों की रक्षा करना ही मनुष्य की निशानी है।

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

डबल इंजन की भाजपा सरकार के प्रयास से स्मार्ट होते शहर

सबका साथ - सबका विकास
सबका विश्वास - सबका प्रयास

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में रहने वाले गरीब/ बेघर/ कम आय वर्ग के लोगों को पक्के आवास उपलब्ध कराये जाते हैं।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना** के अन्तर्गत प्रदेश में **45 लाख 50 हजार** से अधिक आवासों का निर्माण।
- नगरीय क्षेत्र में **17 लाख 05 हजार आवासों** का निर्माण ।
- शहरी लाभार्थियों के खाते में **27,727 करोड़ रु.** की धनराशि ऑनलाइन हस्तान्तरित।
- वर्ष 2019 व 2021 में उत्तर प्रदेश **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन** करने वाला राज्य।
- आवास निर्माण एवं डी.बी.टी. के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण में **उत्तर प्रदेश** का **देश में प्रथम स्थान।**
- लखनऊ में **ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज** पर आधारित **लाइट हाउस प्रोजेक्ट** के अन्तर्गत 1040 आवासों का निर्माण।
- प्रयागराज में **एफोर्डेबुल रेन्टल हाउसिंग कॉम्पलेक्स** का निर्माण।
- मलिन बस्तियों का चरणबद्ध तरीके से पुनर्वास कर सभी पात्र स्लम परिवारों को बुनियादी सुविधाएं एवं पक्के आवास उपलब्ध कराने हेतु **उत्तर प्रदेश स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति-2021** लागू।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

योजना के अन्तर्गत **रेहड़ी/पटरी/ठेला** लगाने वाले लोगों (पथ विक्रेताओं) को **रोजी-रोजगार** के लिए **10,000 रु.** का **ब्याज अनुदान आधारित ऋण** उपलब्ध कराया जाता है।

- प्रथम ऋण की वापसी के उपरान्त द्वितीय ऋण **20,000 रु.** एवं द्वितीय ऋण की वापसी के उपरान्त **50,000 रु.** का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- अब तक **8,56,594** व्यक्तियों को प्रथम ऋण, **1,13,908** व्यक्तियों को द्वितीय ऋण एवं **340** व्यक्तियों को तृतीय ऋण प्रदान करते हुए **1086 करोड़ रु.** का ऋण वितरित किया गया।
- योजना के क्रियान्वयन एवं ऋण वितरण में **उत्तर प्रदेश** का **देश में प्रथम स्थान।**

नगरीय परिवहन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलेक्ट्रिक बसों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करते हुए।

- **फेम इण्डिया स्कीम-2** के अन्तर्गत **लखनऊ** में **100**, **वाराणसी** में **50**, **कानपुर** में **80**, **आगरा** में **85**, **प्रयागराज** में **50**, **गोरखपुर** में **25**, **गाजियाबाद** में **30**, **मथुरा-वृन्दावन** में **50**, **अलीगढ़** में **23**, **बरेली** में **15**, **मेरठ** में **30**, **मुरादाबाद** में **15**, **शाहजहांपुर** में **10** और **झांसी** में **25 इलेक्ट्रिक बसें** संचालित।
- **फेम इण्डिया-1 स्कीम** के अन्तर्गत लखनऊ में **40 इलेक्ट्रिक बसें** संचालित।
- **फेम इण्डिया स्कीम-2** के अन्तर्गत **लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद** एवं **झांसी** में **600 इलेक्ट्रिक बसों** हेतु भारत सरकार द्वारा तथा **गोरखपुर, शाहजहांपुर** एवं **मथुरा-वृन्दावन** में **100 इलेक्ट्रिक बसों** हेतु प्रदेश सरकार द्वारा **अनुदान** स्वीकृत।
- **फेम इण्डिया स्कीम-2** के अन्तर्गत प्रदेश के 14 शहरों में **जी.सी.सी. (ग्रास कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट) मोड** पर इलेक्ट्रिक बसें संचालित।
- नगरीय क्षेत्रों में **418 सी.एन.जी.** एवं **246 डीजल** (कुल 664) बसें संचालित।
- लखनऊ में **121**, कानपुर में **146**, आगरा में **73** तथा मेरठ में **78 सी.एन.जी बसें** संचालित।
- वाराणसी में **103**, प्रयागराज में **99**, मथुरा-वृन्दावन में **36** तथा मेरठ में **8 डीजल बसें** संचालित।
- बसों की सही लोकेशन हेतु इलेक्ट्रिक बसों में **व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस** स्थापित।
- महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बसों में **सी.सी.टी.वी.** एवं **पैनिक बटन** की व्यवस्था।
- नगरीय बसों के संचालन हेतु **लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, मथुरा, गोरखपुर, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, शाहजहांपुर** व **झांसी** में **एस.पी.वी.** का गठन।
- प्रदेश के **14** नगरों में **आधुनिक इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन** क्रियाशील।
- प्रदेश के 14 शहरों में 04 नोडल पैकेज **(लखनऊ, कानपुर, मेरठ एवं आगरा)** गठित। प्रत्येक पैकेज में **175 इलेक्ट्रिक बसें** संचालित होनी हैं, जिनमें से **625 बसों** की आपूर्ति प्राप्त हो गयी है।
- अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अयोध्या, सहारनपुर एवं झांसी में **कम्प्रीहेन्सिव मोबिलिटी प्लान (सी.एम.पी.)** बनाये जाने की कार्यवाही गतिशील है।

अमृत मिशन

इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति, सीवर कनेक्शन, नलकूप, भूमिगत जलाशय, सीवरेज तथा हरित भूमि व पार्क विकास आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर नगरीय जन-जीवन को बेहतर बनाना है।

पेयजल

- **6150 किमी.** पेयजल वितरण प्रणाली के सापेक्ष **5500 किमी.** पेयजल वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण।
- जलापूर्ति के **10.2 लाख** गृह संयोजन के सापेक्ष **8.45 लाख** गृह संयोजन का कार्य पूर्ण।
- **552 नलकूपों** की स्वीकृति के सापेक्ष **अब तक 501 नलकूप** निर्मित।
- 132 भूमिगत जलाशयों की स्वीकृति के सापेक्ष **अब तक 98** जलाशय निर्मित।
- 5 नगरीय निकायों में **405 एम.एल.डी.** क्षमता के डब्ल्यू.टी.पी. के सापेक्ष 4 नगरीय निकायों में **345 एम.एल.डी.** क्षमता के डब्ल्यू. टी.पी. का निर्माण गतिमान। 60 एम.एल.डी. क्षमता के 1 डब्ल्यू. टी.पी. का निर्माण पूर्ण।

सीवरेज

- **3361 किमी.** नेटवर्क के सापेक्ष **2278 किमी.** का कार्य पूर्ण।
- **8.39 लाख** गृह संयोजन के सापेक्ष **6.81 लाख** गृह संयोजन का कार्य पूर्ण।
- 13 नगरीय निकायों में **408 एम.एल.डी.** के 14 एस.टी.पी. के सापेक्ष **139 एम.एल.डी. क्षमता** के **6 एस.टी.पी.** का कार्य पूर्ण।
- प्रदेश में **58 एस.टी.पी.** में शोधन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए **ओ.सी.ई.एम.एस.** (Online Continuous Emission Monitoring Systems) की परियोजना कुल **15.46 करोड़ रु.** की लागत से अमृत कार्यक्रम में क्रियान्वित की जा रही है।

हरित भूमि और पार्क विकास

- **341** परियोजनाओं के सापेक्ष **260** पार्क/परियोजनाएं पूर्ण।

अमृत 2.0 मिशन

- सभी नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं अमृत शहरों में सीवरेज, पार्क, अमृत सरोवरों के निर्माण आदि के लिए **32,000 करोड़ रु.** भारत सरकार द्वारा स्वीकृत।
- पहले चरण के लिए **8200 करोड़ रु.** की 105 परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत।

एकता सरोवर पार्क, पीलीभीत

मेट्रो रेल सेवा

- लखनऊ महानगर में **एयरपोर्ट** से **मुंशी पुलिया** तक लगभग **23 किमी. मेट्रो रेल सेवा** संचालित।
- **चारबाग स्टेशन** से **बसन्त कुंज** तक **मेट्रो रेल सेवा (ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर)** का कार्य शीघ्र प्रारम्भ होगा।
- नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक **29.7 किमी. मेट्रो रेल सेवा (एक्वा लाइन)** संचालित।
- नोएडा सिटी सेन्टर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक डी.एम.आर.सी ब्लू लाइन का 6.9 किमी. विस्तार/संचालन।
- ओखला बर्ड सैंक्चुरी व बोटेनिकल गार्डेन तक डी.एम.आर.सी मैजेंटा लाइन का विस्तार/संचालन।
- **गाजियाबाद** व **कानपुर** में मेट्रो रेल सेवा संचालित।
- **आगरा** में मेट्रो रेल सेवा का कार्य गतिमान।
- गाजियाबाद में वैशाली से मोहन नगर तथा सेक्टर-62 नोएडा से इन्दिरापुरम होते हुए साहिबाबाद तक मेट्रोलाइट सेवा चलाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
- दिल्ली से मेरठ के लिए सुगम यातायात हेतु **रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम** (आर.आर.टी.एस.) का विकास।
- **गोरखपुर मेट्रो लाइट परियोजना** के कार्यों का शुभारम्भ।
- **काशी, मेरठ, बरेली, झांसी** और **प्रयागराज** में **मेट्रो लाइट** अथवा **मेट्रो नियो** परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु डी.पी.आर. की कार्यवाही।

दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

- **36,746** स्वयं सहायता समूहों का गठन कर **3,67,460** शहरी गरीब परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ा गया। गठित समूहों को **25 करोड़ 61 लाख रिवॉल्विंग फण्ड** के रूप में अवमुक्त।
- शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण हेतु **245 करोड़ रु.** की **60** योजनाएं स्वीकृत। अब तक **136** परियोजनाओं का कार्य पूर्ण।
- **8 हजार 759** शहरी विक्रेताओं हेतु **55 वेंडिंग जोन** निर्माण के लिए **17 करोड़ 80 लाख रु.** की परियोजनाएं स्वीकृत। अब तक **08 वेंडिंग जोन** के निर्माण का कार्य पूर्ण।
- **89,068** लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया एवं **34,608** लाभार्थियों को सेवायोजित किया गया।
- स्वरोजगार हेतु **47,687** गरीब परिवारों को एकल ऋण, **1210** को समूह ऋण एवं **8,998** स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरित।

मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना

- योजना के अन्तर्गत नवसृजित/ सीमा विस्तारित/ उच्चीकृत नगर निकायों में मूलभूत नगरीय सुविधाओं यथा मार्ग निर्माण, जल निकासी/नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक केन्द्र व पार्क आदि के निर्माण/उच्चीकरण के लिए **550 करोड़ रु.** का प्रावधान किया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन

योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास यथा जलापूर्ति, विद्युत-आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, स्वच्छता, सुगम परिवहन, मार्ग, पार्किंग, पथ-प्रकाश, आईटी. कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस और स्वच्छ पर्यावरण आदि कार्य किये जाते हैं।

इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर, प्रयागराज

केन्द्र पुरोनिधानित योजना :

- **आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर** व **वाराणसी** में स्वच्छता, जलापूर्ति, पथ-प्रकाश, सीवरेज आदि नागरिक सुविधाओं के साथ स्मार्ट मार्ग, स्मार्ट पार्किंग, पार्कों एवं वॉटर बॉडीज के विकास की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है
- योजना के अन्तर्गत **9572 करोड़ रु.** की लागत से **542** कार्यों की स्वीकृति के सापेक्ष **4757 करोड़ रु.** के **343** कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं **4815 करोड़ रु.** के **199** कार्य प्रगति पर हैं।
- **लगभग 2000 करोड़ रु.** की लागत से 10 नगरों में **इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर** एवं **इन्टेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम** क्रियाशील हैं।
- **इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के माध्यम से** प्रयागराज कुम्भ एवं कोविड-19 का सफल प्रबंधन।
- **हैबिटैट सेन्टर** अलीगढ़ का कार्य पूर्ण।
- स्मार्ट सिटी रैंकिंग में **आगरा व वाराणसी** प्रथम 10 शहरों में सम्मिलित।

राज्य स्मार्ट सिटी योजना

- राज्य सरकार द्वारा भी **अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ** व **शाहजहांपुर** को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- **अयोध्या, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ** एवं **शाहजहांपुर** में **271 करोड़ रु.** की लागत से **इन्टेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम** (आई.टी.एम.एस.) का कार्य प्रगति पर है।
- **मथुरा-वृन्दावन, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद** व **अयोध्या** में **253 करोड़ रु.** की लागत से स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट मार्ग, स्मार्ट क्लास व हरित शवदाह गृह निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- **28 करोड़ रु.** की लागत से राज्य स्तर पर **क्लॉउड आधारित स्मार्ट सिटी सेन्ट्रल डिजिटल मॉनिटरिंग** का कार्य पूर्ण।

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)

- **2 करोड़ 61 लाख शौचालयों (इज्जत घर)** का निर्माण कर **10 करोड़ लोग** लाभान्वित।
- सम्पूर्ण प्रदेश **ओ.डी.एफ.** घोषित।
- नगरीय क्षेत्र में **8,99,634 व्यक्तिगत शौचालयों** एवं **69,381 सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों** का निर्माण।
- महिलाओं हेतु **3670** सीट के पब्लिक/कम्युनिटी/पिंक टॉयलेट का निर्माण।
- **12,022 वार्डों** में 100 प्रतिशत **डोर-टू-डोर कूड़े** का कलेक्शन।
- **सिंगल यूज प्लास्टिक** प्रतिबन्धित। **1468 टन** प्लास्टिक जब्त तथा **16.27 करोड़ रु.** का जुर्माना।
- 28 शहरों में **353 करोड़ रु.** की लागत से **4030 टी.पी.डी.** क्षमता के **सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट** स्थापित। अब सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग की क्षमता **8510 टी.पी.डी.** हो गयी है।
- आगरा में **पी.पी.पी. मॉडल** पर **280 करोड़ रु.** से **वेस्ट टू इनर्जी प्लांट** की स्थापना।
- 22 स्थानीय निकायों में **22 लाख टन** क्षमता के **लिगेसी वेस्ट रिमिडियेशन प्लांट** क्रियाशील।
- 75 नगरीय निकायों में एकत्रित **89,21,000 टन लिगेसी वेस्ट** में से **51,21,000 टन लिगेसी वेस्ट** का निस्तारण। शेष के निस्तारण का कार्य प्रक्रियाधीन।
- गाजियाबाद, प्रयागराज व वाराणसी में **650 टी.डी.पी.** के **वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट** की स्थापना।
- प्रयागराज एवं मथुरा में **वेस्ट प्लास्टिक टू फ्यूल प्लांट** की स्थापना।
- गाजियाबाद में गार्बेज फैक्ट्री/प्लास्टिक म्यूजियम का निर्माण।
- वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद व प्रयागराज में **मैकेनाइज्ड क्लीनिंग** की व्यवस्था।
- लखनऊ, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, मेरठ व वाराणसी में **वेस्ट प्लास्टिक से सड़क निर्माण।**
- **राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति** लागू।
- स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश राज्य को वर्ष 2020 में **20 अवार्ड** तथा वर्ष 2021 में **37 अवार्ड** प्राप्त हुए।

लोकहित के अन्य महत्वपूर्ण कार्य

- अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन एवं शाहजहांपुर में नये नगर निगम का गठन।
- 113 नये नगर निकायों का गठन।
- आउटसोर्स सफाई कर्मियों के न्यूनतम पारिश्रमिक में **9 प्रतिशत** की वृद्धि।
- **लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, बरेली, मथुरा-वृन्दावन** व **कन्नौज** में **नई टाउनशिप** की मंजूरी।
- लखनऊ में **ग्रीन कॉरिडोर** के अन्तर्गत गोमती नदी के तटबन्धों पर **चार लेन सड़क** के निर्माण की योजना।
- लखनऊ स्थित वृन्दावन योजना में 25 एकड़ भूमि पर **5 हजार सीटों** वाले **कन्वेंशन सैंटर** के निर्माण का निर्णय।
- **आसरा योजना** के अन्तर्गत **10,832 आवासों** का निर्माण।
- **जे.एन.एन.यू.आर.एम.** में **5,868 आवासों** का निर्माण।
- वाराणसी में गंगा नदी के किनारे **100 हेक्टेयर क्षेत्रफल** में **टैंट-सिटी** की परिकल्पना।
- **प्रयागराज कुम्भ-2019** का सफल आयोजन।
- एस.टी.पी. एवं शहरों की सीवरेज प्रणाली में मैन्युअल कार्य पद्धति के स्थान पर मशीनरी एवं साइंटिफिक कार्य पद्धति हेतु **वन सिटी-वन ऑपरेटर** योजना लागू।
- 60 शहरों में **ई-नगर** सेवा लागू।
- जन्म-मृत्यु के पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था।
- सम्पत्ति कर/म्यूटेशन की ऑनलाइन व्यवस्था।
- लखनऊ एवं गाजियाबाद नगर निगम द्वारा म्युनिसिपल बॉण्ड जारी।
- कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु योजना के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कुल **521 गौ आश्रय स्थल** (स्थायी+अस्थायी) संचालित।
- 320 छोटी नगर पालिकाओं में आधारभूत सुविधाओं हेतु **720 करोड़ रु.** निर्गत।
- नगरीय झील/पोखर/तालाब संरक्षण हेतु **200 करोड़ रु.** की **504 परियोजनाएं** स्वीकृत।
- **1000 अमृत सरोवरों** का कार्य पूर्ण।
- **311 नगरीय निकायों** में अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण/जीर्णोद्धार/सुन्दरीकरण हेतु **208 करोड़ रु.** निर्गत।
- नगरीय पेयजल की 160 परियोजनाओं हेतु **280 करोड़ रु.** निर्गत।
- **48,000** गरीबों को स्वरोजगार हेतु **545 करोड़ रु.** अनुदान आधारित ऋण वितरित।
- **दशाश्वमेघ घाट** के विकास का कार्य गतिमान।
- अयोध्या में **स्प्रिचुअल सिटी** के अन्तर्गत सूर्य मन्दिर के रेस्टोरेशन का कार्य।
- **मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना** के अन्तर्गत 47 करोड़ रु.से सी.सी.रोड/इण्टरलॉकिंग, नाली, पेयजल एवं मार्ग प्रकाश आदि कार्य।
- संभव पोर्टल के माध्यम से लोक शिकायतों का तेजी से निस्तारण।
- जनशिकायतों के निवारण हेतु 1533 टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर।

मुद्रक : गौस्पेल प्रेस, लखनऊ

राष्ट्रवादी भाजपा

काम से अपने लुभाती राक्ट्रवादी भाजपा।
देश का गौरव बढ़ाती राक्ट्रवादी भाजपा।।

राजाभइया गुप्ता 'राजाभ'

साथ रिपु के कार्य-वाणी से खड़े जब दल कई,
तब सबक अरि को सिखाती, राष्ट्रवादी भाजपा।
देश में अधिकांश दल परिवार हित ही सोंचते,
राष्ट्र-हित खुद को खपाती, राष्ट्रवादी भाजपा।।1।।

पूर्ण वैभव लक्ष्य लेकर चल रही है देश-हित,
सीख कल से कल सजाती, राष्ट्रवादी भाजपा।
शेष दल जब स्वार्थ में ही कार्यरत है देखिए,
देश-हित जनमत बनाती, राष्ट्रवादी भाजपा।।2।।

अब नहीं अवहेलना होती सनातन धर्म की,
मान उसको है दिलाती, राष्ट्रवादी भाजपा।
लोग हैं कुद बात झूठी बोल मन-बल तोड़ते,
किन्तु साहस-बल बढ़ाती, राष्ट्रवादी भाजपा।।3।।

व्यक्ति के हो लो विरोधी राष्ट्र के तो मत बनों,
है इसी का लाभ पाती राष्ट्रवादी भाजपा।
देशद्रोही लोग जो भी साथ रिपु के हैं खड़े,
आइना उनको दिखाती राष्ट्रवादी भाजपा।।4।।

जब निराशा को बढ़ाने में जुटे जयचन्द तब,?
देश में आशा जगाती राष्ट्रवादी भाजपा।
हीनता अब कम हुई गौरव बढ़ाया विश्व में,
देश का डंका बजाती राष्टवादी भाजपा।।5।।

गैस, बिजली और शौचालय खुशी दे दीन का,
है सुगम जीवन बनाती राष्ट्रवादी भाजपा।
दे बना घर, धूप-वर्षा-शीत की चिन्ता हरे,
कष्ट दीनों का मिटाती, राष्ट्रवादी भाजपा।।6।।

पंथ के कारण सताए जो गए परदेश में,
मान दे उनको बसाती, राष्ट्रवादी भाजपा।
वोटवादी नीतियों ने जो बढ़ायीं दूरियाँ,
जाति-पंथों में मिटाती, राष्ट्रवादी भाजपा।।7।।

है सनातन धर्म को अब आप से आशा बहुत,
आज की पीढ़ी लगाती, राष्ट्रवादी भाजपा।
खींचकर ढोंगी मुखौटा सत्य लाती सामने,
जेल भी उनको कराती राष्ट्रवादी भाजपा।।8।।

हो पड़ोसी धूर्त तो कैसे निपटना? जानती,
पाठ भी है कटु पढ़ाती, राष्ट्रवादी भाजपा।
सामने कितना बड़ा भी हो खड़ा यदि सूरमा,
दाब में बिलकुल न आती राष्ट्रवादी भाजपा।।9।।

हो न पायी शीघ्र अब तक न्याय की उपलब्धता,
है तभी निज को बचाती राष्ट्रवादी भाजपा।
राष्ट्र-द्रोही काँप जाएं द्रोह के पहले सदा,
क्यों न विधि ऐसी बनाती? राष्ट्रवादी भाजपा।।10।।

सि) है इतिहास से जब शत्रु हैं जो जन्म से,
दूध उनको क्यों पिलाती? राष्ट्रवादी भाजपा।
आसतीनों के सपोले और जो गद्दार हैं,
जेल उनको क्यों न लाती, राष्ट्रवादी भाजपा।।11।

जब सनातन को सताते हैं विधर्मी हो अभय,
देखकर भी मुँह छुपाती, राष्ट्रवादी भाजपा।
दृष्टि है 'राजाभ' की भी सत्य जो कुछ सामने,
है उसी को ही बताती, राष्ट्रवादी भाजपा।।12।।

शब्द माधुर्य की अभिलाषा

श्री हृदय नारायण दीक्षित

सतत् संवाद लोकतंत्र का प्राण हैं। संवादरत समाज गतिशील होते हैं। संवाद से सामाजिक परिवर्तन होते हैं। संवाद का मुख्य उपकरण भाषा है। प्रख्यात भाषाविद मोलनीविसी ने 1923 में कहा था कि ''भाषा सामाजिक संगठन का काम करती है।'' दुनिया के सभी समाज भाषा के सदुपयोग द्वारा ही गढ़े गए हैं। ज्ञान, विज्ञान, इतिहास और दर्शन भाषा के कारण सार्वजनिक सम्पदा बनते हैं। इसके लिए सार्वजनिक बहसों की गुणवत्ता जरूरी होती है। लेकिन भारतीय राजनीति में सार्वजनिक बहसों का स्तर लगातार गिर रहा है। सर्वोच्च न्यायपीठ ने भी सार्वजनिक बहस के गिरते स्तर पर बेबाक टिप्पणी की है। न्यायालय ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते सोमवार को कहा, ''यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक गिरा देंगे तो आपको अंजाम भुगतने होंगे।'' सिसोदिया ने प्रेस वार्ता में असम के मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी पर पी०पी०ई० किट की खरीद पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। झूठे आरोपों से आहत हेमंत ने स्थानीय न्यायालय में मानहानि का मुकदमा किया। सिसोदिया प्राथमिकी खारिज कराने के लिए पहले हाईकोर्ट गए। फिर सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक बहस के गिरते स्तर पर टिप्पणी की। सिसोदिया ने मानहानिकारक टिप्पणियां की थी। सार्वजनिक बहसों में शब्द सदुपयोग और वाक् संयम की मर्यादा का हनन हो रहा है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की अपील से देश स्तब्ध है। यद्यपि उन्होंने बाद में इसका स्पष्टीकरण भी दिया है। लेकिन उनका मूल वक्तव्य भयावह है। उच्चस्तरीय सार्वजनिक बहसें आदर्श लोकमत बनाती हैं। इससे सामाजिक परिवर्तन के अनेक द्वार खुलते हैं। प्रत्येक दल, समूह, नेता या सामाजिक कार्यकर्ता के अपने विचार होते हैं। अपनी विचारधारा के पक्ष में लोकमत बनाना सबका अधिकार है। संविधान निर्माताओं ने इसीलिए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बनाया। लेकिन भारत की सम्प्रभुता, अखण्डता और लोक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली अभिव्यक्ति पर मर्यादा और संयम के बंधन भी लगाए। वाक् संयम और प्रेमपूर्ण शब्द प्रयोग सार्वजनिक बहसों का सौंदर्य है। सम्प्रति सार्वजनिक बहसों के गिरते स्तर से दल समूहों के मध्य परस्पर घृणा का भाव पैदा हो रहा है। दल समूह परस्पर शत्रु नहीं होते। लेकिन घृणा और विद्वेष के कारण दल तंत्र में शत्रुता का भाव बढ़ा है। पतन की श्रंखला बन चुकी है। पहले अपशब्द प्रयोग से घृणा बढ़ती है। फिर सभी पक्षों में परस्पर शत्रु भाव विकसित होता है। फिर झूठ फरेब का आचरण और छल कपट बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में होने वाली बहसों में परस्पर अपशब्द कहने के दृश्य देखे सुने जा रहे हैं। दलतंत्र के प्रति जनतंत्र का सम्मान घटा है। बहसों में उपयुक्त शब्द प्रयोग की महत्ता है। प्रत्येक शब्द के गर्भ में भाव और अर्थ होता है। संयम विहीनता के कारण भाव दुर्भाव में प्रकट हो रहा है और अर्थ का अनर्थ हो रहा है। शब्द और अपशब्द का भेद मिट रहा है। बेशक बहसों में असहमति व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। लेकिन असहमति प्रकट करने में अपशब्दों का प्रयोग जरूरी नहीं होता। मानहानिकारक शब्दों से बचा जा सकता है। सम्मानजनक अभिव्यक्ति के माध्यम से असहमति प्रकट करना ही सम्मानजनक तरीका है। लोकसभा में परमाणु परिक्षण पर बहस हो रही थी। चन्द्रशेखर ने अटल

> ''यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक गिरा देंगे तो आपको अंजाम भुगतने होंगे।''

बिहारी वाजपेयी सरकार पर कुछ टिप्पणियां की। अटल जी ने कहा कि ''परमाणु परीक्षण पर चन्द्रशेखर जी ने विचार व्यक्त किए हैं। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है।'' आखिरकार अपशब्द प्रयोग की अनिवार्यता क्या है? प्रश्न अनेक हैं। क्या भारतीय भाषाओं में सम्मानजनक विरोध प्रकट करने के लिए शब्द सामर्थ्य की कमी है? क्या अपमानजनक शब्द प्रयोग से ही सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन संभव है? क्या चुनावी जीत के लिए व्यक्तिगत आरोपों का कोई विकल्प नहीं? क्या विपक्षी उम्मीदवार को अपशब्द कहने से वोट बढ़ते हैं? सार्वजनिक बहसों को निम्नस्तरीय बनाने वाले मित्रों में भाषा ज्ञान की दरिद्रता है। भारतीय चिंतन में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। महाभारत युद्ध में व्यास ने आहत मन होकर कहा था कि शब्द अब ब्रह्म नहीं रहे। आज की स्थिति भी ऐसी ही है।

मानहानिकारक शब्द प्रयोग से शब्द का मूल अर्थ और सौंदर्य खो जाता है। पतंजलि ने शब्द प्रयोग में सतर्कता के निर्देश दिए थे, ''शब्द का सम्यक ज्ञान और सम्यक प्रयोग ही अपेक्षित परिणाम देता है।'' अपशब्द आत्मीय शब्दों का विकल्प नहीं हो सकते। अपशब्द प्रयोग का अंतिम परिणाम हिंसा है। बहस के स्तर की गिरावट से सांस्कृतिक सामाजिक सौहार्द नष्ट हो रहा है। सामाजिक समूह एक दुसरे को शत्रु भाव से देखते हैं। सुन्दर शब्द प्रयोग जीवन रस को प्रभावित करते हैं और समाज को आनंदित करते हैं। शब्दों का दुरूपयोग विनाशकारी है। सुन्दर ढंग से प्रयुक्त किए गए शब्द मंत्र हो जाते हैं। सार्वजनिक बहसों में अपशब्दों की आग बरस रही है। शब्द अंगार हो रहे हैं। जो जितना जोर बोले, जो जितने अपशब्द बोले, मानहानिकारक शब्द प्रयोग करे, वह उतना ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जल और वायु की तरह अपशब्द प्रदूषण भी बढ़ा है। अपशब्द प्रदूषण ने सार्वजनिक जीवन की छंदबद्धता व लय को नष्ट कर दिया है। कभी कभी जल्दबाजी में उपयुक्त शब्द नहीं निकलते लेकिन सार्वजनिक जीवन के अति प्रतिष्ठित लोग भी सुनियोजित ढंग से सोच समझ कर ही अपशब्द बोल रहे हैं। राष्ट्र की क्षति हो रही है।

सार्वजनिक बहसों के गिरते स्तर का सीधा प्रभाव संसदीय संस्थाओं पर भी पड़ा है। संसद और विधान मण्डल देश के भाग्य विधाता हैं। तीसरी चैथी लोकसभा तक संसद में सुन्दर शब्द बोलने की प्रतिस्पर्धा थी।

सार्वजनिक बहसों के गिरते स्तर का सीधा प्रभाव संसदीय संस्थाओं पर भी पड़ा है। संसद और विधान मण्डल देश के भाग्य विधाता हैं। तीसरी चैथी लोकसभा तक संसद में सुन्दर शब्द बोलने की प्रतिस्पर्धा थी। अब परिदृश्य बदल गया है। शब्द प्रयोग में शालीनता और संयम का अभाव दिखाई पड़ता है। परस्पर तू तू मै मै के दृश्य भी दिखाई देते हैं। विधान मण्डलों की स्थिति भी चिंताजनक है। राष्ट्रजीवन में निराशा व चिंता बढ़ी है। संसद सार्वजनिक बहसों को उच्चस्तरीय व प्रेरक बनाने का मंच भी है। लोकसभा से गाँव सभा तक सार्वजनिक बहसों की चिंताजनक धारा है। यह सब उस देश में हो रहा है जहां हजारों वर्ष पहले सभा और समितियों में सुन्दर बोलने की प्रतिस्पर्धा थी। शब्द माधुर्य की अभिलाषा सहस्त्रों वर्ष पहले ऋग्वेद, अथर्ववेद के रचनाकाल में भी थी। ऋग्वेद में प्रार्थना है कि ''हमारा पुत्र सभा में सुन्दर बोले। यशस्वी हो।'' अथर्ववेद (9–1) में स्तुति है – हमारी जिह्वा का अग्रभाग मधुवाणी से युक्त हो। मूल भाग भी मधुर हो। हम तेजस्वी वाणी भी मधुरता के साथ बोलें। वाणी मधुर हो।'' वैदिक साहित्य में मंत्रों के छोटे समूह को सूक्त कहते हैं। सूक्त का अर्थ सु – उक्त (सुन्दर कथन) है। तब सुंदर कथन की अनिवार्यता थी। लुडविग जैसे विद्वानों के अनुसार वैदिक काल में सभा और समितियां महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेमपूर्ण बहस करती थीं। उत्तर वैदिक काल में शास्त्रार्थ परंपरा में भी परस्पर आत्मीयता थी। लेकिन आधुनिक भारत में सार्वजनिक बहसों में व्यक्तिगत आक्षेपों, उत्तेजक मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। देश के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं व भिन्न भिन्न क्षेत्रों के शीर्ष महानुभावों को सार्वजनिक बहसों को शालीन बनाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता

श्रीमती मीना चौबे

(भारतीय जनता पार्टी) का एक ही लक्ष्य है पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के 'अंत्योदय' के सिद्धांत पर विकास की दृष्टि से सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की प्रथम पंक्ति में लाना और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार इसी दिशा में प्रयासरत है। देश की सुरक्षा, सतत विकास और पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर देने वाली भारत माता की दैदीप्यमान छवि के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास व अर्थव्यवस्था के सभी मापदंड सुदृढ़ हुए है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक सर्वस्पर्शी एवं सर्व–समावेशक विकास के मॉडल की स्थापना की है । सरकार की 150 से अधिक लोक–कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रबंध किया।देश में 60 साल से अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी की शासन रही है ।लेकिन देश की आधी आबादी के पास अपना बैंक अकाउंट तक नहीं था, माताएं लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाने के लिए विवश थी, घरों में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी और आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18 हजार गाँव अंधेरे में जीने को मजबूर थे। मोदी सरकार ने 45 करोड़ से अधिक लोगों को 'जन–धन' योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ा है, लगभग चार करोड़ महिलाओं को गैस सिलिंडर उपलब्ध कराया है, साढ़े सात करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है और बिजली से वंचित गाँवों को रोशन करने का काम किया है। आपको स्मरण होगा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने एलपीजी पंचायत आयोजित करके एक ही दिन में 11 लाख गैस सिलिंडर वितरित किये जो अपने–आप में एक रिकॉर्ड है। साथ ही 12 करोड़ से अधिक महिलाएं रसोई गैस सिलेंडर उज्ज्वला के माध्यम से पाकर अपनी धुंए भरी जिंदगी से मुक्त हो गयी है। वैसे ही पहले जहां सरकारें कुछ गाँवों में बिजली उपलब्ध कराने की योजनायें बनाती थी, वहीं आज सरकार की सोच है कि सौभाग्य योजना से देश का कोई भी ऐसा गाँव न बचे जहां बिजली न हो।स्टार्ट–अप, स्टैंड–अप, स्किल डेवलपमेंट और मुद्रा योजना के माध्यम से देश के लगभग 12 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गए हैं।केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना के तहत लगभग 73% ऋण महिलाओं को उपलब्ध कराये गए हैं जो उनकी आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार ने कई कार्य किये हैं। मोदी सरकार ने पॉस्को एक्ट में बदलाव कर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार पर कड़ा रुख इख्तियार करते हुए एक गंभीर कदम उठाकर महिलाओ को सुरक्षा देने का कार्य किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण, बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ, मुद्रा बैंक योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्टैंड–अप योजना, स्टार्ट–अप योजना, मातृत्व अवकाश, बच्चों का टीकाकरण अभियान, कौशल विकास, नई रोशनी, उड़ान जैसी कई योजनायें महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार द्वारा उठाये गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं एवं उनके जीवन–स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मैं तो कहती हूँ कि समानता के तथाकथित बात करने वाले लोगो से वो हमें सीख न दें, हम तो उस संस्कृति से आते हैं, जहां माताओं को देवी का स्थान दिया गया है, वेद की ऋचाओं तक में कहा गया है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः'। हमारी संस्कृति समानता से भी कही आगे है जहां माताएं सर्वप्रथम होती है, उनका स्थान कहीं उंचा होता है। श्री नरेन्द्र मोदी के रूप में हमसबके बीच में आज देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो खुद बेटियों को बचाने और बेटियों को पढ़ाने के लिए अपनी झोली फैलाकर निकलते हैं, जो खुद शौचालय के निर्माण की योजना बनाते हैं और उज्ज्वला जैसी योजनाओं के माध्यम से उनके सशक्तिकरण का अभियान छेड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी की पहल का सकारात्मक परिणाम समाज में आ रहा है और महिलायें सशक्त बन कर देश के थल जल नभ तक के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है।भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी सफलता के लिए राजनीति नही करती बल्कि देश को विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने और विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए राजनीति करती है ।भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य देश के हर गरीब को रोटी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा "सबका–साथ सबका–विकास सबका–विश्वास व सबका–प्रयास के मंत्र के साथ–साथ सभी को संविधान में प्रदत्त सभी अधिकार उपलब्ध कराना है।

नव्य भारत का खुशहाल संकल्प सिद्धि

एक भारत श्रेष्ठ भारत की आकांक्षा अन्त्योदय का संकल्प, प्राणियों में सद्भावना थी अभिलाषा लिये नरेन्द्र मोदी जी की सरकार भारत की खुशहाली देने में लगी है। ऐसे में मोदी जी मन की बात के माध्यम से पाथेय देते रहते हैं। ऐसे में उन्होने शासन की उपलब्धियां बताई। हमारा मंत्र होना चाहिए: 'बेटा बेटी एक समान' "आइए कन्या के जन्म का उत्सव मनाएं। हमें अपनी बेटियों पर बेटों की तरह ही गर्व होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर आप पांच पेड़ लगाएं।" – प्रधान मंत्री ने अपने गोद लिए गांव जयापुर के नागरिकों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरूआत प्रधान मंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन–काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। यह ...

जनता को मिली JAM की ताकत: जन धन, आधार और मोबाइल :–

श्र।ड का विजन, आगामी कई पहलों के लिए बुनियाद का काम करेगा। मेरे लिए श्र।ड का मतलब है अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति। खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये का अधिकतम प्रतिफल। हमारे गरीबों का अधिकतम सशक्तिकरण। जनता के बीच तकनीक का अधिकतम प्रसार। –नरेंद्र मोदी आजादी के 67 साल बाद भी भारत में बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी जिन्हें बैंकिंग सेवाएं नहीं हासिल थीं। इसका मतलब है कि उनके पास न तो बचत कोई जरिया था, न ही संस्थागत कर्ज पाने का कोई अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बुनियादी मसले का समाधान करने के लिए 28 अगस्त को जन धन योजना की शुरुआत की। कुछ ...

विकास के प्रति नवीन दृष्टिकोण: सांसद आदर्ष ग्राम योजना :–

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के शुभारंभ पर अपना विचार साझा किया। 'हमारे लिए एक बड़ी समस्या रही है कि हमारा विकास आपूर्ति–उन्मुख रहा है। लखनउ, गांधी नगर अथवा दिल्ली में एक स्कीम तैयार की गई है। इसे ही आरंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आदर्श ग्राम के द्वारा इस माडल को आपूर्ति–उन्मुख की बजाए मांग–उन्मुख करना चाहते हैं। स्वयं ग्राम में ही इसकी इच्छा विकसित की जानी चाहिए। हमें केवल अपने विचार में परिवर्तन करना है। हमें लोगों के दिलों को जोड़ना है। सामान्यतः, सांसद राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। लेकिन इसके ...

भारतीय उद्यमियों के हौसले हुए बुलंद :–

मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत में बहुत अधिक मात्रा में छिपी हुई उद्यमशील उर्जा है। इसे पोषित–पल्लवित करने की जरूरत है, ताकि हम नौकरी चाहने वाले देश से आगे बढ़कर नौकरी देने वाला देश बनें। –नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। 'मेक इन इंडिया' पहल भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के हमारे चार स्तंभों पर आधारित है। ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी। नई कार्यविधि: 'मेक इन इंडिया' उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' ...।

नमामि गंगे :–

उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर स्थित वाराणसी से संसद के लिए मई 2014 में निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, 'मां गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है।' गंगा नदी का न सिर्फ़ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। 2014 में न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, "अगर हम इसे साफ करने में सक्षम हो गए तो यह देश की 40 फीसदी आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। अतः गंगा की सफाई एक आर्थिक।

भारत के विकास को मिली मज़बूती :–

भारत ने 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का महत्वाकांक्षी

मिशन तय किया है। ये गांव आजादी के 7 दशक बाद आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। प्रधान मंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि 1000 दिनों के भीतर सभी शेष गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। गांवों का विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है। और, यह काम बहुत ही पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। एक मोबाइल ऐप और एक वेब डैशबोर्ड के जरिए विद्युतीकरण किए जा रहे गांवों के आंकड़े जनता के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि हम गांवों में केवल बिजली को ...

योग के नियमित अभ्यास से, Breast Cancer के मरीजों की बीमारी के, फिर से उभरने और मृत्यु के खतरे में, 15 प्रतिशत तक की कमी आई है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में यह पहला उदाहरण है, जिसे, पश्चिमी तौर-तरीकों वाले कड़े मानकों पर परखा गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज हुई रफ्तार :–

एनडीए सरकार के तहत भारत दुनिया में सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक साल था। पस्त पड़ चुकी विकास दर, भारी महंगाई और उत्पादन में कमी के दौर से उबरते हुए एनडीए सरकार ने ना सिर्फ मैक्रो–इकनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूत किया, बल्कि अर्थव्यवस्था को एक तेज रफ्तार विकास पथ ले आई। भारत की जीडीपी विकास दर कुलांचे भर कर 7. 4% हो गई, जो दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। विभिन्न रेटिंग एजेंसी और थिंकटैंक ने अनुमान जताया है कि एनडीए सरकार के तहत अगले कुछ वर्षों में भारत का ...

एक खुशहाल भारत के लिए मजबूत किसान :–

कृषि को तेजी से बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए किसान हमेशा से हमारे देश का आधार रहे हैं और एनडीए सरकार इनोवेशन और कुछ ठोस उपायों के जरिए देश के इस आधार को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई की सुविधाएं सुनिश्चित कर उपज को बढ़ाएगी। इस योजना का विजन यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक खेत को किसी ना किसी तरह के सुरक्षात्मक सिंचाई के साधन उपलब्ध हों। किसानों को सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है ताकि पानी की 'प्रत्येक बूंद के बदले अधिक पैदावार' मिले। किसान समूहों ...

कायम की अभूतपूर्व पारदर्शिता :–

देश हित में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पिछले दशक में हालांकि मनमाने ढंग से फैसले लेने, भ्रष्टाचार और मनमाने ढंग से महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कई कहानियां सुनाई दीं, लेकिन पिछले एक वर्ष में स्वगतयोग्य बदलाव देखा गया। कोयला ब्लाक आवंटन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार ने अतुलनीय तत्परता दिखाते हुए पारदर्शी और समयबद्ध नीलामी सुनिश्चित की। 67 कोयला ब्लाक की नीलामी और आवंटन की प्रक्रिया 3.35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा: "हमें इस तथ्य ने आश्वस्त किया है कि नीलामी की प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हुई। ...

एक उज्ज्वल भविष्य की ओर :–

एनडीए सरकार ने शिक्षा तथा कौशल विकास को दिया बेमिसाल बढ़ावा शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए कई यूनीक उपाये किए गए। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से सभी शिक्षा ऋणों और छात्रवृत्तियों के प्रशासन और निगरानी के लिए एक पूर्ण रूप से आईटी आधारित वित्तीय सहायता प्राधिकरण की स्थापना की गई। अध्यापन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण मिशन शुरू किया गया। भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर देने के लिए ग्लोबल इनीशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क (GIAN) की शुरुआत हुई। इसके तहत देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में गर्मी और सर्दी के अवकाश के ...

कायम की अभूतपूर्व पारदर्शिता :–

देश हित में पारदर्शी और

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पिछले दशक में हालांकि मनमाने ढंग से फैसले लेने, भ्रष्टाचार और मनमाने ढंग से महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कई कहानियां सुनाई दीं, लेकिन पिछले एक वर्ष में स्वगतयोग्य बदलाव देखा गया। कोयला ब्लाक आवंटन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार ने अतुलनीय तत्परता दिखाते हुए पारदर्शी और समयबद्ध नीलामी सुनिश्चित की। 67 कोयला ब्लाक की नीलामी और आवंटन की प्रक्रिया 3.35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहाः "हमें इस तथ्य ने आश्वस्त किया है कि नीलामी की प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हुई। ...

एक खुशहाल भारत के लिए मजबूत किसान :—

कृषि को तेजी से बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए किसान हमेशा से हमारे देश का आधार रहे हैं और एनडीए सरकार इनोवेशन और कुछ ठोस उपायों के जरिए देश के इस आधार को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई की सुविधाएं सुनिश्चित कर उपज को बढ़ाएगी। इस योजना का विजन यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक खेत को किसी ना किसी तरह के सुरक्षात्मक सिंचाई के साधन उपलब्ध हों। किसानों को सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है ताकि पानी की 'प्रत्येक बूंद के बदले अधिक पैदावार' मिले। किसान समूहों ...

मेक इन इंडिया :—

विनिर्माण क्षेत्र का दिग्गज बनने की राह में भारत भारत में ना सिर्फ विनिर्माण बल्कि अन्य क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम चार स्तंभों पर आधारित है। नई कार्यविधिः 'मेक इन इंडिया' का मानना है कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात 'कारोबार करने की सुविधा' है। कारोबारी माहौल को आसान बनाने के लिए कई इनीशिएटिव पहले ही षुरू किए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य पूरे कारोबारी चक्र के दौरान इंडस्ट्री को डी—लाइसेंस और डी—रेग्युलेट करना है। नया बुनियादी ढांचाः उद्योगों के विकास के लिए आधुनिक और सुविधाजनक बुनियादी ढांचे ...

जन धन से जन सुरक्षा :—

भारत ने बनाया विश्व कीर्तिमानः अधिकतम संख्या में बैंक खाते खोलने के लिए और सबसे बड़ी कैश ट्रांसफर स्कीम के लिए आजादी के 67 वर्ष बाद भी भारत में बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी, जिन्हें किसी भी तरह की बैंकिंग सेवा उपलब्ध नहीं थी। इसका मतलब था कि उनके पास बचत के लिए कोई जरिया नहीं था, और ना ही संस्थागत कर्ज लेने का कोई मौका था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बुनियादी मसले का समाधान करने के लिए 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की। कुछ ही महीनों में 15 करोड़ बैंक खाते खोले गए। अभी तक ...

एक सुधारवादी कार्यशील सरकार :—

26 मई, 2014 को एनडीए की सरकार बनते ही लोगों की सरकार से उम्मीदें बढ़ गईं। लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने पहले ही दिन से जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरु कर दिया। सरकार विकास को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां और कानून लाने दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को इसकी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सुधारों की एक नई लहर पैदा की जा रही है। भारत के पास आर्थिक क्रांति लाने और लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। एनडीए ...

मिशन मोड में शासन :—

16 मई 2014 भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। जनता ने एक ऐतिहासिक जनादेश दिया था और नरेन्द्र मोदी को अपना प्रधान मंत्री चुना था। ये मतदान एक परिवर्तन के लिए, एक ऐसे नेता के लिए था जो कार्य को संपन्न करने वाले व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है, ये वोट एक ऐसे नेता के लिए था जिसका एकल उददेश्य भारत की प्रगति है। जैसा कि हमेशा से उन्होंने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करके दिखाया है, नरेन्द्र मोदी पहले दिन से ही अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय हो गए। ये बात ...

स्वच्छ भारत की दिशा में पहल :—

नई दिल्ली में राजपथ पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि दे सकता है।" 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। स्वच्छता के लिए जन आंदोलन की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे साफ और स्वच्छ भारत के महात्मा गांधी के सपने को पूरा करें। श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पास सफाई अभियान।

भारत के अध्यक्षता की पारी शुरू

जी20 अध्यक्षता के दौरान हम भारत के अनुभव, ज्ञान और प्रारूप को दूसरों के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए एक संभावित टेम्प्लेट के रूप में प्रस्तुत करेंगे

- नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

जी20 की पिछली 17 अध्यक्षताओं के दौरान वृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतरराष्ट्रीय कराधान को तर्कसंगत बनाने और विभिन्न देशों के सिर से कर्ज के बोझ को कम करने समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे तथा यहां से और आगे की ओर बढ़ेंगे।

अब, जबकि भारत ने इस महत्वपूर्ण पद को ग्रहण किया है, मैं अपने आपसे यह पूछता हूंकृ क्या जी20 अभी भी और आगे बढ़ सकता है? क्या हम समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता में मूलभूत बदलाव को उत्प्रेरित कर सकते हैं?

मेरा विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं।

हमारी परिस्थितियां ही हमारी मानसिकता को आकार देती हैं। पूरे इतिहास के दौरान मानवता अभाव में रही। हम सीमित संसाधनों के लिए लड़े, क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरों को उन संसाधनों से वंचित कर देने पर निर्भर था। विभिन्न विचारों, विचारधाराओं और पहचानों के बीच, टकराव और प्रतिस्पर्धा आदर्श बन गए।

दुर्भाग्य से हम आज भी उसी शून्य–योग की मानसिकता में अटके हुए हैं। हम इसे तब देखते हैं जब विभिन्न देश क्षेत्र या संसाधनों के लिए आपस में लड़ते हैं। हम इसे तब देखते हैं जब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को हथियार बनाया जाता है। हम इसे तब देखते हैं जब कुछ लोगों द्वारा टीकों की जमाखोरी की जाती है, भले ही अरबों लोग बीमारियों से असुरक्षित हों।

कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि टकराव और लालच मानवीय स्वभाव है। मैं इससे असहमत हूं। अगर मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है, तो हम सभी में मूलभूत एकात्मता की हिमायत करने वाली इतनी सारी आध्यात्मिक परंपराओं के स्थायी आकर्षण को कैसे समझा जाए?

भारत में प्रचलित ऐसी ही एक परंपरा है जो सभी जीवित प्राणियों और यहां तक कि निर्जीव चीजों को भी एक समान ही पांच मूल तत्वोंकृ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के पंचतत्व से बना हुआ मानती है। इन तत्वों का सामंजस्यकृ हमारे भीतर और हमारे बीच भीकृ हमारे भौतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण के लिए आवश्यक है।

भारत की जी20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी। इसलिए हमारी थीमकृ 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है। ये मानवीय परिस्थितियों में उन हालिया बदलावों को ध्यान में रखता है, जिनकी सराहना करने में हम सामूहिक रूप से विफल रहे हैं।

आज हमारे पास दुनिया के सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने के साधन हैं।

आज, हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है; हमारे युग को युद्ध का युग होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए!

आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं, बल्कि मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है।

सौभाग्य से आज की जो तकनीक है वह हमें मानवता के व्यापक पैमाने पर समस्याओं का समाधान करने का साधन भी प्रदान करती है। आज हम जिस विशाल वर्चुअल दुनिया में रहते हैं, वह डिजिटल प्रौद्योगिकियों की मापनीयता को प्रदर्शित करती है।

भारत इस सकल विश्व का सूक्ष्म जगत है जहां विश्व की आबादी का छठवां हिस्सा रहता है और जहां भाषाओं, धर्मों, रीति–रिवाजों और विश्वासों की विशाल विविधता है।

सामूहिक निर्णय लेने की सबसे पुरानी ज्ञात परंपराओं वाली

सभ्यता होने के नाते भारत दुनिया में लोकतंत्र के मूलभूत डीएनए में योगदान देता है। लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की राष्ट्रीय सहमति किसी फरमान से नहीं, बल्कि करोड़ों स्वतंत्र आवाजों को एक सुरीले स्वर में मिलाकर बनाई गई है।

आज, भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे प्रतिभाशाली युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा का पोषण करते हुए हमारा नागरिक–केंद्रित शासन मॉडल एकदम हाशिए पर पड़े नागरिकों का भी ख्याल रखता है।

हमने राष्ट्रीय विकास को ऊपर से नीचे की ओर के शासन की कवायद नहीं, बल्कि एक नागरिक–नेतृत्व वाला 'जन आंदोलन' बनाने की कोशिश की है।

हमने ऐसी डिजिटल जन उपयोगिताएं निर्मित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है जो खुली, समावेशी और अंतर–संचालनीय हैं। इनके कारण सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसे विविध क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रगति हुई है।

इन सभी कारणों से भारत के अनुभव संभावित वैश्विक समाधानों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

जी20 अध्यक्षता के दौरान हम भारत के अनुभव, ज्ञान और प्रारूप को दूसरों के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए एक संभावित टेम्प्लेट के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

हमारी जी20 प्राथमिकताओं को न केवल हमारे जी20 भागीदारों, बल्कि वैश्विक दक्षिण में हमारे साथ–चलने वाले देशों, जिनकी बातें अक्सर अनसुनी कर दी जाती है, के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

हमारी प्राथमिकताएं हमारी 'एक पृथ्वी' को संरक्षित करने, हमारे 'एक परिवार' में सद्भाव पैदा करने और हमारे 'एक भविष्य' को आशान्वित करने पर केंद्रित होंगी।

अपने प्लेनेट को पोषित करने के लिए हम भारत की प्रकृति की देखभाल करने की परंपरा के आधार पर स्थायी और पर्यावरण–अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करेंगे।

मानव परिवार के भीतर सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए हम खाद्य, उर्वरक और चिकित्सा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति को गैर–राजनीतिक बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि भू–राजनीतिक तनाव मानवीय संकट का कारण न बनें। जैसा हमारे अपने परिवारों में होता है, जिनकी जरूरतें सबसे ज्यादा होती हैं, हमें उनकी चिंता सबसे पहले करनी चाहिए।

हमारी आने वाली पीढ़ियों में उम्मीद जगाने के लिए हम बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों से पैदा होने वाली जोखिमों को कम करने और वैश्विक सुरक्षा बढ़ाने पर सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के बीच एक ईमानदार बातचीत को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

भारत का जी20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई–उन्मुख और निर्णायक होगा।

आइए, हम भारत की जी20 अध्यक्षता को संरक्षण, सद्भाव और उम्मीद की अध्यक्षता बनाने के लिए एकजुट हों।

आइए, हम मानव–केंद्रित वैश्वीकरण के एक नए प्रतिमान को स्वरूप देने के लिए साथ मिलकर काम करें।

भारत की जी-20 अध्यक्षता पर सर्वदलीय बैठक

जी-20 अध्यक्षता पूरे राष्ट्र की है: नरेन्द्र मोदी

भारत की जी20 अध्यक्षता से जुड़े पहलुओं पर चर्चा करने के लिये पांच दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की। बैठक में देशभर के राजनैतिक नेतृत्व ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता पूरे राष्ट्र की है तथा यह समस्त विश्व के सामने भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने का अनोखा अवसर है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि आज भारत के प्रति दुनिया में जिज्ञासा और आकर्षण है, जिससे भारत की जी20 अध्यक्षता की संभावनायें और प्रबल हो जाती हैं।

प्रधानमंत्री ने टीम वर्क की महत्ता पर जोर दिया और जी20 के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सभी नेताओं के सहयोग की आकांक्षा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जी20 अध्यक्षता एक ऐसा अवसर होगा, जब भारत की छवि पारंपरिक महानगरों से बाहर निकलकर देश के अन्य भागों में परिलक्षित होगी। इस तरह हमारे देश के हर भाग का अनोखापन उजागर होगा।

भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में भारत आने वाले आगंतुकों का उल्लेख करते हुये श्री मोदी ने उन स्थानों पर पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने की क्षमता का उल्लेख किया, जहां जी20 की बैठकें आयोजित की जायेंगी।

प्रधानमंत्री के उद्बोधन के पहले विभिन्न राजनेताओं ने भारत की जी20 अध्यक्षता पर अपने अमूल्य विचार रखे।

गृहमंत्री और वित्तमंत्री ने संक्षेप में अपनी बात रखी। भारत की जी20 अध्यक्षता पर विभिन्न पक्षों को शामिल करते हुये एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी पेश किया गया। बैठक में मंत्रीगण श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्रीमती निर्मला सीतारमण, डॉ. एस. जयशंकर, श्री पीयूष गोयल, श्री प्रह्लाद जोशी, श्री भूपेन्द्र यादव और पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा उपस्थित थे।

नवंबर, 2022 के दौरान सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,45,867 करोड़ रुपए रहा

सकल जीएसटी राजस्व संग्रह में साल-दर-साल 11% की वृद्धि।
लगातार नौ महीने जीएसटी राजस्व संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार नवंबर, 2022 के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व 1,45,867 करोड़ रुपए रहा, जिसमें से सीजीएसटी 25,681 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 32,651 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 77,103 करोड़ रुपए (माल के आयात पर एकत्रित 38,635 करोड़ रुपए सहित) और 10,433 करोड़ रुपए (माल के आयात पर एकत्रित 817 करोड़ रुपए सहित) उपकर है।

केंद्र सरकार ने आईजीएसटी से 33,997 करोड़ रुपए सीजीएसटी के लिए और 28,538 करोड़ रुपए एसजीएसटी के लिए तय किए हैं। नवंबर, 2022 के महीने में नियमित निपटान के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 59,678 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 61,189 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, केंद्र ने नवंबर, 2022 में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 17,000 करोड़ रुपये भी जारी किए थे।

नवंबर, 2022 के महीने का राजस्व पिछले साल इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 11% अधिक है। महीने के दौरान माल के आयात से राजस्व 20% अधिक था और घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 8% अधिक है। उल्लेखनीय है कि लगातार नौ महीने जीएसटी राजस्व संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा।

भारतीय तटरक्षक बल ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एमके-3 के स्क्वाड्रन को सेवा में किया शामिल

भारतीय तटरक्षक बल में चरणबद्ध तरीके से कुल 16 एएलएच एमके-3 हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया है

रक्षा मंत्रालय ने एक दिसंबर को कहा कि भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने चेन्नई में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एमके–3 के स्क्वाड्रन को सेवा में शामिल किया है, जिससे सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सुदूर अपतटीय क्षेत्र में बल की क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 840 स्क्वॉड्रन (सीजी) को शामिल किया जाना इस बात का संकेत है कि हेलीकॉप्टर निर्माण के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से अग्रसर है और यह प्रयास केंद्र सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना के अनुरूप है।

बयान में कहा गया कि तटरक्षक क्षेत्र पूर्वी, 840 स्क्वॉड्रन (सीजी) को और मजबूत करने के बड़े प्रयास के तहत उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) एमके–3 स्क्वॉड्रन को महानिदेशक वी.एस. पठानिया ने 30 नवंबर, 2022 को आईसीजी वायु स्टेशन, चेन्नई में सेवा में शामिल किया। इसमें कहा गया कि इस स्क्वाड्रन को सेवा शामिल करने से सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सुदूर अपतटीय क्षेत्र में बल की क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी।

बयान के अनुसार, एएलएच एमके–3 हेलीकॉप्टरों को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने निर्मित किया है, जो पूरी तरह स्वदेशी हैं। इनमें उन्नत रडार के साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल संवेदी यंत्र, शक्ति इंजन, पूरी तरह शीशे का बना कॉकपिट, तेज प्रकाश वाली सर्च लाइट, उन्नत संचार प्रणालियां, स्वचालित पहचान प्रणाली, तलाश व बचाव प्रणालियां लगी हैं।

मंत्रालय के अनुसार, इन उपकरणों और सुविधाओं की सहायता से हेलीकॉप्टर समुद्री टोही गतिविधियों के अलावा काफी दूर तक तलाशी व बचाव कार्य कर सकता है। हेलीकॉप्टर दिन और रात, दोनों समय पोतों से उड़ान भरकर इन गतिविधियों को अंजाम देने में सक्षम है।

बयान में कहा गया कि हेलीकॉप्टर में भारी मशीनगन लगी हुई है और यह पलक झपकते आक्रामक मुद्रा में आ सकता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इसमें एक गहन चिकित्सा सुविधा इकाई भी मौजूद है, ताकि गंभीर रूप से बीमार मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके।

भारतीय तटरक्षक बल में चरणबद्ध तरीके से कुल 16 एएलएच एमके–3 हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया है। इनमें से चार हेलीकॉप्टरों को चेन्नई में तैनात किया गया है। शामिल होने के बाद से स्क्वॉड्रन ने 430 घंटों से अधिक समय की उड़ान भरी है तथा अनेक संचालन अभियानों को पूरा किया है।

विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत किया

वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल घटनाक्रमों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती दिखा रही है तथा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहेगा

वश्वि बैंक ने चालू वित्त वर्ष (2022–23) के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया। विश्व बैंक ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल घटनाक्रमों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती दिखा रही है।

विश्व बैंक ने छह दिसंबर को जारी भारत से संबंधित अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं। इस वजह से पूरे वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाया जा रहा है।

पिछले वित्त वर्ष (2021–22) में भारत की वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत रही थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी जुलाई–सितंबर की तिमाही में अर्थव्यवस्था 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। वहीं, जून तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 13.5 प्रतिशत रही थी।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच यह किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का भारत की वृद्धि दर के बारे में पहला अनुमान है। विश्व बैंक की 'तूफान में आगे बढ़ना' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक हालात खराब होने का असर भारत की वृद्धि संभावनाओं पर पड़ेगा। हालांकि, अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक झटकों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है।

इसके साथ ही विश्व बैंक का यह भी मानना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहेगा।

विश्व बैंक के भारत में निदेशक तानो कुआमे ने कहा कि बाहरी परिदृश्य खराब होने के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था जुझारू क्षमता दिखा रही है और वृहद आर्थिक बुनियाद मजबूत होने की वजह से अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की स्थिति अच्छी है।

रिपोर्ट में कहा गया कि 2023–24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहेगी। विश्व बैंक ने यह भी भरोसा जताया कि सरकार चालू वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लेगी।

2023–24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहेगी। विश्व बैंक ने भरोसा जताया कि सरकार चालू वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लेगी।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11 अरब डॉलर बढ़कर 561.16 अरब डॉलर पर

देश का विदेशी मुद्रा भंडार दो दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 11.02 अरब डॉलर बढ़कर 561.162 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नौ दिसंबर को यह जानकारी दी।

विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार चौथे सप्ताह तेजी आई है। पिछले सप्ताह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.9 अरब डॉलर बढ़कर 550.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। वहीं 11 नवंबर को समाप्त सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 14.72 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी। एक सप्ताह में दूसरी बार सबसे अधिक वृद्धि हुई थी।

विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार चौथे सप्ताह तेजी आई है। पिछले सप्ताह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.9 अरब डॉलर बढ़कर 550.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। वहीं 11 नवंबर को समाप्त सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 14.72 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी। एक सप्ताह में दूसरी बार सबसे अधिक वृद्धि हुई थी

केंद्रीय बैंक ने कहा कि कुल मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा माने जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) दो दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 9.694 अरब डॉलर बढ़कर 496.984 अरब डॉलर हो गईं। डॉलर में अभिव्यक्त किये जाने वाले विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पौंड और येन जैसे गैर अमेरिकी मुद्राओं में आई घट–बढ़ के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है।

इसके अलावा स्वर्ण भंडार का मूल्य आलोच्य सप्ताह में 1.086 अरब डॉलर बढ़कर 41.025 अरब डॉलर हो गया।

वीर बाल दिवसः बलिदान को नमन व प्रेरणा लेने का दिन

डॉ. पवन सिंह

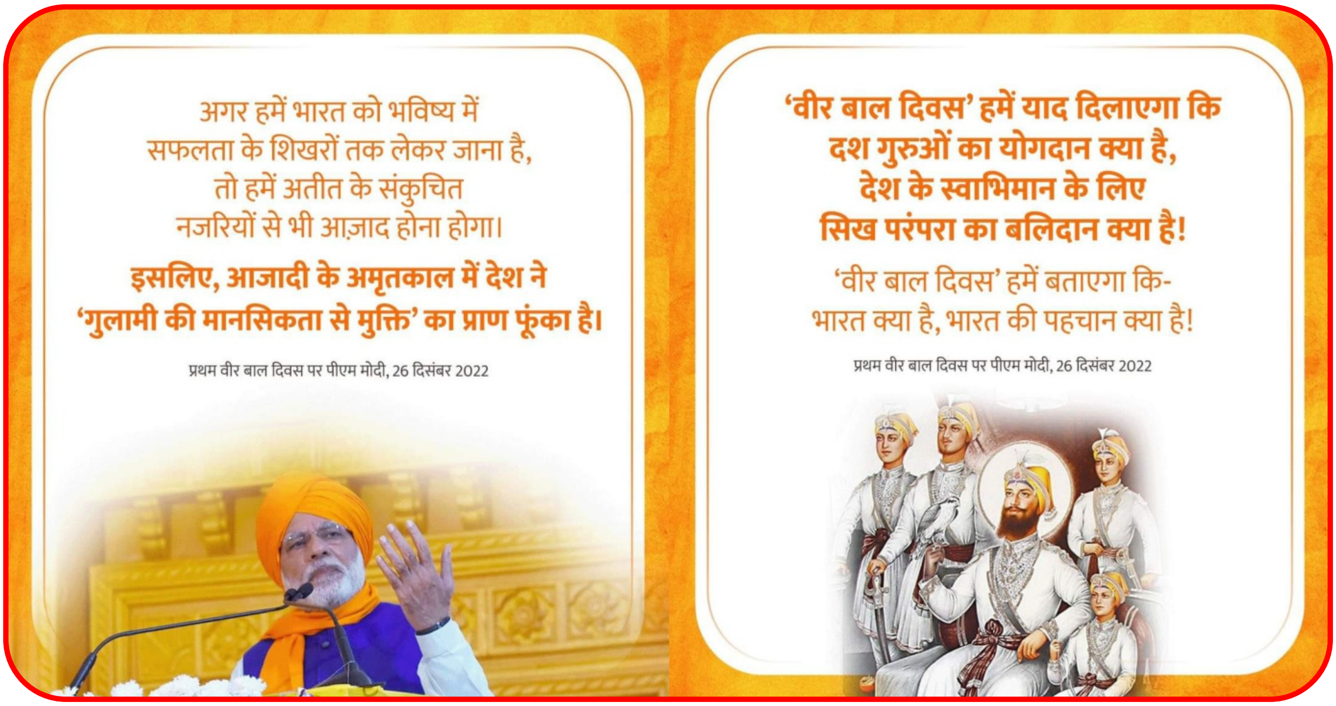

सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का स्मरण आते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। गुरु गोविंद सिंह भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले उन महानायकों में से हैं जिन्होंने हमारे लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। सिख इतिहास शहीदियों की लाजवाब मिसाल है। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्रों "साहिबजादों" के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिये "वीर बाल दिवस" के रूप में चिह्नित किया गया है। यह दिन वास्तव में उनकी शहादत को नमन करने व उनके जीवन से प्रेरणा लेने का दिन है।

सरसा नदी पर बिछड़ गया परिवारः

20 दिसम्बर 1704 की वो रात गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार और 400 अन्य सिखों के साथ आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया था। उस रात भयंकर सर्दी थी और बारिश हो रही थी। सेना 25 कि ।मी ।दूर सरसा नदी के किनारे पहुंची ही थी कि मुगलों ने रात के अंधेरे में धोखे से आक्रमण कर दिया। बारिश के कारण नदी में उफान था कई सिख बलिदान हो गए, कुछ नदी में बह गये। इस अफरा तफरी में परिवार बिछड़ गया। माता गुजरी और दो छोटे साहिबजादे गुरु जी से अलग हो गये। दोनों बड़े साहिबजादे गुरु जी के साथ ही थे।

बड़े साहिबजादों, अजीत सिंह और जुझार सिंह जी का बलिदानः

उस रात गुरु जी ने एक खुले मैदान में शिविर लगाया अब उनके साथ दोनों बड़े साहिबजादे और कुछ सिख योद्धा थे। अगले दिन जो युद्ध हुआ उसे इतिहास मे **Battle of Chamkaur Sahib** के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी 40 सिख फौजों के साथ चमकौर की गढ़ी एक कच्चे किले में 10 लाख मुगल सैनिकों से मुकाबला करते हैं एक–एक सिख दस लाख मुगलिया फौज पर भारी पड़ता है गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े बेटे जिनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की है साहेबजादा अजित सिंह ने मुगल फौजों में भारी तबाही की, सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतारा लेकिन दस लाख मुगलिया फौजों के सामने साहेबजादा अजित सिंह बलिदान हो गए। छोटे साहिबजादे जिनकी उम्र मात्र 14 वर्ष की है,बड़े भाई के बलिदान को देखते हुए पिता गुरु गोविंद सिंह जी से युद्ध के मैदान में जाने की अनुमति मांगी एक पिता ने अपने हाथों से पुत्र को सजाकर युद्ध के मैदान में भेजा लाखों मुगलों पर भारी साहेबजादा जुझार सिंह ने युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिये और लड़ते –लड़ते वीरगति को प्राप्त हूए।

दीवार में जिंदा चुने गए, पर धर्म नहीं बदला :

साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह सिख धर्म के सबसे सम्मानित शहीदों में से हैं। मुगल सैनिकों ने औरंगजेब (1704) के आदेश पर आनंदपुर साहिब को घेर लिया। गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों को पकड़ लिया गया। मुसलमान बनने पर उन्हें न मारने की पेशकश की गई थी। वजीर खां ने फिर पूछा, बोलो इस्लाम कबूल करते हो? छः साल के छोटे साहिबजादे फ़तेह सिंह ने नवाब से पूछा अगर मुसलमान हो गए तो फिर कभी नहीं मरेंगे न? वजीर खां अवाक रह गया उसके मुँह से जवाब न फूटा तो साहिबजादे ने जवाब दिया कि जब मुसलमान हो के भी मरना ही है, तो अपने धर्म में ही अपने धर्म की खातिर क्यों न मरें। दोनों साहिबजादों को ज़िंदा दीवार में चिनवाने का आदेश हुआ। दीवार चिनी जाने लगी। जब दीवार 6 वर्षीय फ़तेह सिंह की गर्दन तक आ गयी तो 8 वर्षीय जोरावर सिंह रोने लगा। फ़तेह ने पूछा, जोरावर भाई रोते क्यों है। जोरावर बोला, रो इसलिए रहा हूँ कि दुनियां में आया मैं पहले था पर कौम के लिए शहीद तू पहले हो रहा है। इन दोनों बालकों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। उसी रात माता गुजरी ने भी ठंडे बुर्ज में प्राण त्याग दिए। दिसंबर मास के इस अंतिम सप्ताह को भारत के इतिहास में 'शहीदी सप्ताह' के रूप में मनाया जाता है।

प्रेरणा व संदेश का दिनः

दिसंबर के इस अंतिम सप्ताह में श्रद्धावानों द्वारा ज़मीन पर सोने की परंपरा है। क्योंकि माता गूजरी ने 25 दिसम्बर की वो रात दोनों छोटे साहिबजादों के साथ वजीर ख़ाँ की गिरफ्त में सरहिन्द के किले में ठंडी बुर्ज़ में गुजारी थी और 26 दिसम्बर को दोनो बच्चे शहीद हो गये थे। 27 तारीख को माता गुजरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। नानकशाही कैलेंडर के अनुसार श्रद्धालु 20 से 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह भी मनाते हैं। इस अवसर पर गुरुद्वारों व घरों में कीर्तन और पाठ करते हैं। साथ ही बच्चों को गुरु साहिब के परिवार की शहादत के बारे में भी जानकारी दी जाती है। गुरु पुत्रों के बलिदान की यह कहानी आज की पीढ़ी को अपने देश से, धर्म से, संस्कृति से व अपने वतन से प्रेम करने का सन्देश देती है।

आज का दिन साहिबजादों के साहस और न्याय के प्रति उनके संकल्प के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। माता गुजरी, गुरु गोबिंद सिंह जी एवं चारों साहिबजादों की वीरता तथा आदर्श लोगों को साहस व शक्ति प्रदान करते हैं। वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसे विश्व की कल्पना की, जो समावेशी और सामंजस्यपूर्ण हो। यह समय की मांग है कि अधिक से अधिक लोग उनके बारे में जाने। आइये, वीर बाल दिवस पर गुरु पुत्रों के प्रेरक जीवन चरित्र को जन– जन तक पहुंचाएं।

लेखक जे.सी. बोस विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के मीडिया विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है।

सामूहिकता का भाव

पं. दीनदयाल उपाध्याय

अब आज एक सज्जन का मैंने लेख पढ़ा। वह विदेशों में घूम करके आए। बड़े दु:खी हुए, कहने लगे, बड़ी मुश्किल है। क्यों, पूछने पर बोले, 'हिंदुस्तान के बारे में सब जगह यह धारणा हो गई है कि भिखारियों का देश है।' तो मैंने कहा, 'भई, तुमने जाकर कोई भीख मांगी क्या?' बोले कि नहीं, मैंने तो भीख नहीं मांगी, परंतु देश भीख मांग रहा है। अब देश भीख मांगता है तो उसको धक्का लगता है। देश में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई और हमारी सेनाएं आगे बढ़ीं तो कोई अगर अमेरिका के अंदर भी था तो वह भी अपना सीना तानकर चलता था। उसको भी लगता था कि वाह वाह! हमारी जीत हो रही है और आपको भी लगता था यहां पर। हालांकि, मैं समझता हूं कि यहां पर आपमें से न कोई मोरचे पर था और न लड़ाई लड़ी। नारे–वारे जरूर लगाए होंगे थोड़ेक़ बहुत, परंतु बाक़ी कुछ नहीं। परंतु मोरचे पर लड़नेवाले सिपाही के गौरव से अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करते थे। इस प्रकार से हमारा गौरव उसके साथ है। राष्ट्र के गौरव में हमारा गौरव है और अलग–अलग इसका विचार किया तो समझ लीजिए कि फिर कभी गौरव होगा नहीं।

आदमी इस सामूहिक चीज़ को भूल जाता है और फिर अकेला–अकेला जब सोचने लगता है तो नुकसान हो जाता है। कभी–कभी ऐसा हो जाता है कि या तो आदमी को समझ में न आए या आदमी को कहीं कुछ कमजोरी नज़र आ जाए तो फिर वह सोचता है कि बाक़ी को छोड़ो, अपने को क्या, इसकी चिंता करो। जब अपनी चिंता करने के लिए आदमी जाएगा तो समझ लीजिए, फिर अव्यवस्था हो जाएगी। जब हम सब सामूहिक रूप से अपना–अपना काम करके राष्ट्र की चिंता करेंगे तो सबकी व्यवस्था हो जाएगी। यह मूलभूत बात है कि हम सामूहिक रूप से विचार करें, व्यक्ति के नाते से नहीं और फिर समाज के नाते से विचार करने के बाद ही उसके लिए हमने जो कुछ किया, उस समाज के काम को पूरा करने के लिए किया। हमने जो कुछ किया, उसी में हमारी बहादुरी, उसी में हमारा गौरव और वास्तव में हमारा व्यक्तिगत बड़प्पन भी उसी में है। उसके अतिरिक्त नहीं।

उसके लिए अगर हमने जीवन लगाया, तो हमारा बड़प्पन। वैसे तो आख़िर को शरीर तो नश्वर है, हरेक का शरीर जाता है, परंतु भगतसिंह को सब लोग याद करते हैं, हकीकत राय को याद करते हैं, गुरुतेग बहादुर को याद करते हैं। आज बलिदानी महापुरुषों को याद करते हैं, क्यों? उनका तो शरीर गया। शरीर की रक्षा करनी हरेक चाहता है, किंतु फिर भी उन्होंने अपना शरीर गंवा दिया। उनके बलिदान को कोई आत्महत्या नहीं कहता। सभी कहते हैं कि भाई, उन्होंने बलिदान किया। इसलिए कोई कहे कि क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली? आत्महत्या और बलिदान इसमें अगर अंतर है तो इतना ही कि जब शरीर देश के लिए दिया जाए, समाज के काम में लगाया जाए, राष्ट्र के लिए लगाया जाए, तो वह बलिदान है और उसको लोग याद करते हैं। उससे देश ऊपर उठता है। उससे समाज को ताकत मिलती है और इसके विपरीत अगर कोई भी काम किया जाए तो वह फिर समाज के लिए घातक हो जाता है। वह फिर नुकसान की चीत होती है। तो समाज का विचार, यह सदैव करके काम करना चाहिए। यह एक मूलभूत बात है।

हमारा आर्थिक विकास, हमारा राष्ट्रीय विकास, हमारा नैतिक विकास, हमारा आध्यात्मिक विकास सबका सब समाज के साथ जुड़ा हुआ है, यानी आध्यात्मिक विकास भी कोई अपना जो है, हिमालय की गुफाओं में जाकर के योगाभ्यास कर ले और सोचे कि उसे मुक्ति मिल जाएगी, तो नहीं मिल सकती। अगर किसी को योगाभ्यास करना है तो योगाभ्यास कर ले, परंतु योगाभ्यास के द्वारा जो उसको सिद्धि प्राप्त हुई है, उस सिद्धि से अगर वह समाज को ऊंचा नहीं उठा सकता तो उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति के विषय में अपने यहां पर कुछ लोगों की ग़लत धारणा हो गई कि मुक्ति कोई व्यक्तिगत चीज है। व्यक्तिगत मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं। मुक्ति जो है, यह भी सामाजिक है, समष्टिगत है और उसी में से जब समाज मुक्त होगा, समाज ऊंचा उठेगा तो फिर व्यक्ति भी ऊंचा उठेगा, उसे मुक्ति मिलेगी।

समाज का काम करनेवाला ही सर्वोपरि है। केवल जिन्होंने

अपना यानी समाज का काम छोड़ दिया, उन्होंने तो धर्म छोड़ दिया। लोकमान्य तिलक ने जो 'गीता रहस्य में एक जगह लिखा, उन्होंने बताया शास्त्रों का पुराना श्लोक, सुभाषित उन्होंने उसमें दिया–

अपहाय वियज कर्म कृष्ण कृष्यति प्रतिवादिनाम्।
तेदामाः धर्म विनाश का धर्माधर्म जन्मपद धारय।।

अर्थात् जो अपना धर्म छोड़ करके और जो कृष्ण–कृष्ण चिल्लाते रहते हैं, वे धर्म का विनाश करनेवाले हैं और उसका कारण बताया कि स्वयं कृष्ण समाज का काम करनेवाला है। भगवान् ने धर्म की रक्षा करने के लिए, काम करने के लिए जन्म लिया। अगर केवल नाम स्मरण से सब कुछ हो जाता तो भगवान् जन्म काहे को लेते, उनको जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों जन्म लिया तो धर्म की रक्षा करने के लिए। भगवान् के जितने भी अवतार हुए, किसी अवतार का यह वर्णन नहीं आता कि उन्होंने जाकर किसी गुह्य में बैठकर योगाभ्यास किया हो। भगवान् कृष्ण ने तो जीवन भर काम किया उन्होंने कर्म किया और संपूर्ण समाज को अपने सामने रखकर काम किया। यह उनके जीवन की विशेषता है।

समाज के लिए काम भगवान् का काम है और केवल अपने लिए काम वास्तव में यह शैतान का काम है। तो भगवान् की भक्ति अगर कोई है, तो वह है राष्ट्र की भक्ति यानी समाज की भक्ति यही भगवान् का काम है। इसी में से व्यक्तिगत महत्ता प्राप्त होती है, व्यक्ति ऊंचा होता है। हमारा नाम हमारा सम्मान, हमारी सब चीजें इसमें अंतर्निहित हैं। महाभारत के युद्ध को देखें, तो एक बार उसमें बड़े मजे की चीज़ आई है। लोगों के सामने समस्या भी आकर खड़ी हो जाती है तो वहां पर यह कहा है कि धर्ममय बनो और कहा कि जहां धर्म है, वहीं जीत होती है। अब जीत किसकी हुई? तो पांडवों के साथ धर्म था, इसमें तो कोई दो मत नहीं हो सकते, क्योंकि पांडवों की जीत हुई, पर फिर एक बार सवाल आया और ऐसे ही पूछा कि भाई, ऐसी बात है कि पांडवों और कौरवों की जो लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में कौरव पक्ष का ऐसा एक भी योद्धा नहीं है, जिसको किसी–न–किसी चालाकी से न मारा गया हो, हरेक को चालाकी से मारा गया। आप जानते हैं, भीष्म की मृत्यु कैसे हुई, शिखंडी को खड़ा करके; उसके पीछे से अर्जुन ने बाण चलाए और भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए, तब जा करके भीष्म पितामह युद्ध से आहत होकर के शर–शय्या पर लेट गए। द्रोणाचार्य को मृत्यु कैसे हुई? युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति ने झूठ बोला और कहा, 'अश्वत्थामा हतो वा नरो व कुञ्जरो' यानी अश्वत्थामा मारा गया। यह घोषणा कर दी तो बेचारे द्रोणाचार्य अपने पुत्र के शोक में व्याकुल होकर के युद्ध से विरक्त हो गए और तभी द्रोणाचार्य मारे गए। कर्ण मारा गया, जब उसके रथ का पहिया धंस गया था, उसको कर्ण निकालने लगा था। उसके ऊपर बाण चलाया गया। यहां कर्ण का वध हुआ। इसी तरह दुर्योधन भी मारा गया। दुर्योधन, जब गदा युद्ध हो रहा था, तब युद्ध के नियम के प्रतिकूल दुर्योधन की जंघा पर भीम के वार करने से मारा गया। नियम ऐसा है कि 'बिलो दि बेल्ट' प्रहार नहीं करना। यह नियम अपने यहां भी पुराना है। जंघा के ऊपर वार करना चाहिए, पर भीम ने जंघा पर ही वार किया और भगवान् कृष्ण ने उसको इशारा करके बताया कि जंघा पर वार करो। इस वार के कारण दुर्योधन मर गया। अब सवाल पैदा होता है कि यह तो सब छलछद्म है। पांडवों ने सब छलछद्म किया ही क्यों? युधिष्ठिर का झूठ बोलना धर्म है। वह जो जयद्रथ का वध किया और सारे आकाश में सूर्य छिप गया बादलों में। जयद्रथ को लगा कि सूर्य छिप गया है। वह बेचारा बाहर आया और बाद में वास्तव में सूर्य छिपा नहीं था, एकदम से फिर वह आया और उसके बाद जयद्रथ का वध कर दिया। यह कोई धर्म है? गदायुद्ध में जंघा पर वार करना कोई धर्म है? शिखंडी के पीछे खड़े होकर अर्जुन जैसा महारथी भीष्म के ऊपर बाण चलाए, यह धर्म है? लगता है कि यह तो सब अधर्म है।

व्यक्तिगत मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं। मुक्ति जो है, यह भी सामाजिक है, समष्टिगत है और उसी में से जब समाज मुक्त होगा, समाज ऊंचा उठेगा तो फिर व्यक्ति भी ऊंचा उठेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। समाज का काम करनेवाला ही सर्वोपरि है

यह अधर्म होने के बाद की जीत है और फिर भी हम कहते हैंकृ'यतो धर्मस्ततो 'जयः।' ऐसा लगता है कि महाभारतकार ने भी सबसे बड़ा धोखा दिया है। धर्म के नाम पर अधर्म के प्रचार का प्रयास किया है या फिर कहने में कहीं गलती की है। जो विचार करें, एक बात पता लगेगी और वह यह कि कौरव पक्ष और पांडव पक्ष में अगर कोई बात एक थी तो वह यह कि कौरव पक्ष का हर व्यक्ति व्यक्तिवादी था, समष्टिवादी नहीं था। समाज का विचार करने के लिए तैयार नहीं था। वहां पर भीष्म पितामह इतने बड़े थे, परंतु 'मैं'कृमैंने प्रतिज्ञा की है कि शिखंडी के आने के बाद मैं बाण नहीं चलाऊंगा। और भाई, आप सेनापति हो, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का महत्त्व है कि सेनापति के कर्तव्य का? दूसरी तरफ अर्जुन भी तो कह सकता था कि दुनिया में कोई मुझे क्या कहेगा? अर्जुन जैसा गांडीवधारी और वह शिखंडी की ओट में बाण चलाए, यह क्या अर्जुन के लिए शोभा देगा? अर्जुन के नाम पर कलंक है। परंतु कोई चिंता की बात नहीं है। अर्जुन ने समाज का, समष्टि का पूरे अपने पक्ष का विचार किया और भीष्म पितामह ने 'मैं' का विचार किया। उनके सामने व्यक्तिगत प्रतिज्ञा का महत्त्व था।

–शीत शिविर वर्ग, बौद्धिक वर्गः फरवरी 4,1968

कार्यालय शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

37

अटल
स्वास्थ्य
मेला 3

भारतीय जनता पार्टी
उत्तर प्रदेश

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91 डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2021-23
दिसम्बर द्वितीय अंक 2022 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 26–29 (द्वितीय पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित। सम्पादक : अरूण कान्त त्रिपाठी